● वर्ष-3
● अंक-252
रायपुर, शुक्रवार
31 मई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पृथ्वी का आखिरी देश, यहां केवल ...

दो दिन पहले पहुंचा मानसून

नई दिल्ली। आम तौर पर, मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है और 5 जून तक पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ जाता है। हालांकि, इस बार मौसमी बारिश दक्षिण भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग एक ही समय पर शुरू हुई है। यह सामान्य तिथि से दो दिन पहले केरल पहुंचा, जबकि पूर्वोत्तर में यह छह दिन पहले पहुंचा। इसकी शुरुआत आईएमडी के 31 मई (+/-4 दिन) के पूर्वानुमान के अनुरूप है।

यह लक्षद्वीप क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। गुरुवार को मानसून की उत्तरी सीमा दक्षिण में कन्नूर (केरल), कोयंबटूर और कन्याकुमारी (तमिलनाडु) और पूर्व में अगरतला (त्रिपुरा), धुबरी (असम) से होकर गुज़रेगी। गुरुवार को मानसून की उत्तरी सीमा दक्षिण में कन्नूर (केरल), कोयंबटूर और कन्याकुमारी (तमिलनाडु) और पूर्व में अगरतला (त्रिपुरा), धुबरी (असम) से होकर गुज़रेगी। 1970 से 2019 तक आईएमडी द्वारा बनाए गए लंबी अवधि के रिकॉर्ड के अनुसार, मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में आता है और 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर करता है। हालाँकि, मौसम संबंधी स्थितियों में साल-दर-साल बदलाव के कारण यह तिथि हर साल बदलती रहती है। इसलिए, मौसम विभाग ने बादल छाए रहने, हवा के दबाव, नमी की मात्रा जैसी कुछ पूर्वनिर्धारित स्थितियाँ निर्धारित की हैं, जिनकी वह शुरुआत की तारीख घोषित करने से पहले निगरानी करता है। इस मानदंड को 2016 में संशोधित किया गया था, और अब यह केरल और पड़ोसी क्षेत्र के 14 स्टेशनों की दैनिक वर्षा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर पवन क्षेत्र और आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन पर आधारित है.

केरल और पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दी दस्तक

दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, नरेला सबसे गर्म

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान मई के दिन पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। वहीं, मौसम विभाग के शहरी केंद्रों में नरेला सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार रहा। अगले दो दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए लू का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि, रविवार को हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। इससे लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिल सकती है। गुरुवार को दिनभर सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह से ही घरों में कैद रहे। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, दिल्ली का अधिकतम तापमान 45.6 और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नरेला में 49 के पार पहुंचा पारा

मौसम विभाग के मुताबिक नरेला इलाका सर्वाधिक गर्म रहा। यहां अधिकतम 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं, मुंगेशपुर और नजफगढ़ में 49, पीतमपुरा में 48.4 व पूसा में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया।

सामान्य से पांच डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 13 साल में पहली बार 30

महोबा में लू और बुखार से मासूम समेत 14 की मौत

महोबा जिले में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े जानलेवा बन गए हैं। गुरुवार को लू व बुखार की चपेट में आने से मासूम समेत 14 लोगों की मौत हो गई। तीन दिन के अंदर गर्मी से 28 लोगों की जान चुकी है। वहीं 14 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उनका जिला अस्पताल के वार्डों में चल रहा है।

बस खाई में गिरी, 22 की मौत, 69 लोग घायल

जम्मू । जम्मू-पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग (144ए) पर अखनूर के चूंगी मोड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 69 यात्री घायल हो गए। इनमें 57 को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया और 12 लोगों का इलाज अखनूर उपजिला अस्पताल में जारी है। बस में 91 यात्री सवार थे। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा बचाव अभियान चलाया। खाई से निकाल कर घायलों को अखनूर उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) रेफर किया गया।

बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवखोड़ी जा रहे थे यात्री

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उत्तरप्रदेश के हाथरस की यह बस हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शिवखोड़ी धाम जा रही था। शिवखोड़ी धाम, जम्मू संभाग के रियासी जिले के पौनी में स्थित है, जो कि कटड़ा सिथ्त माता वैष्णो देवी मंदिर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है।

जानकारी के अनुसार, बस का नंबर है- यूपी 86ईसी 4078 बताया गया है। यह बस अखनूर के चूंगी मोड़ में गहरी खाई में जा गिरी। इस तीखे मोड़ पर सामने से आ रही एक बस के आने से हादसे वाली बस के चालक का संतुलन बिगड़ा गया और यह दुर्घटना हो गई। बस के गिरते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचित किया गया। तुरंत में राहत और बचाव अभियान चलाया गया। अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों में से एक अमर चंद ने बताया, एक कार विपरीत दिशा से आ रही थी। बस चालक ने तीखा मोड़ को पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप वाहन खाई में जा गिरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) फैसल कुरैशी, परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और अभियान की निगरानी की। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, एसएसपी-जम्मू और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने घायलों के बारे में जानकारी लेने के लिए जीएमसी अस्पताल का दौरा किया। बस के शीशे तोड़ कर लोगों को बाहर निकाला गया। फिर रस्सी और कुछ को पीठ पर लाद कर सड़क तक पहुंचाया गया।

7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार खत्म, 57 सीटों पर शनिवार को मतदान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार गुरुवार, 30 मई को समाप्त हो गया। शीर्ष राजनीतिक दलों के नेताओं ने अंतिम समय में रैलियों के साथ अपने प्रयास तेज कर दिए थे। सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 57 संसदीय क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह-तेरह, पश्चिम बंगाल में नौ, बिहार में आठ, ओडिशा में छह, हिमाचल प्रदेश में चार, झारखंड में तीन और चंडीगढ़ में एक सीट पर एक जून को मतदान होना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। इसके अलावा, ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होनी थी। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट पर मतदान हो चुका है। पहले छह चरणों में मतदान क्रमशः 66.14 प्रतिशत, 66.71, 65.68, 69.16, 62.2 और 63.36 फीसदी रहा।

कन्याकुमारी पहुंचे मोदी, भगवती अम्मन मंदिर के किए दर्शन

विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे 45 घंटे का ध्यान

नई दिल्ली। श्रद्धेय हिंदू संत के नाम पर प्रसिद्ध, मध्य समुद्र स्मारक पर मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भाजपा नेताओं ने कहा था कि मोदी आज लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन के बाद स्वामी विवेकानन्द को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के लंबे ध्यान सत्र के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम पास के तिरुवनंतपुरम से पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना की। बाद में उनका विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचने और लगभग दो दिनों तक ध्यान करने का कार्यक्रम है।

1 जून को अपने प्रस्थान से पहले, मोदी के स्मारक के बगल में तिरुवल्लुवर प्रतिमा का दौरा करने की संभावना है। स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे-छोटे टापुओं पर बनाए गए थे, जो समुद्र में अलग-अलग और टीले जैसी चट्टानी संरचनाएँ हैं। श्रद्धेय हिंदू संत के नाम पर प्रसिद्ध, मध्य समुद्र स्मारक पर मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

भाजपा नेताओं ने कहा था कि मोदी आज लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन के बाद स्वामी विवेकानन्द को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे।

प्रमुख समाचार

अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का दूसरा निजी क्षेत्र का रॉकेट

हरिकोटा। भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी 'अग्निकुल कॉसमॉस' चार असफल प्रयासों के बाद अपना 'अग्निबाण' रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने में सफल रही है. यह अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला दूसरा भारतीय निजी क्षेत्र का रॉकेट है. 'अग्निबाण' में ऐसा भारतीय रॉकेट इंजन लगा हुआ है जो गैस और लिक्विड ईंधन दोनों पर चलता है. यह भारत में इस तरह का एकलौता इंजन है. इसे दो चरणों में लॉन्च किया जाता है और यह 300 किलो तक का भार उठा सकता है. अग्निबाण को लॉन्च करने की कोशिश बीते दो महीनों में कई बार की गई, लेकिन हर बार किसी ना किसी तकनीकी खराबी की वजह से उसे टालना पड़ा. दो ही दिन पहले, मंगलवार को, भी लॉन्च की कोशिश की गई थी, लेकिन लिफ्ट-ऑफ से पांच सेकंड पहले रद्द करना पड़ा. मील का पत्थर गुरुवार को यह रॉकेट लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में 700 किलोमीटर ऊंचाई तक गया और करीब दो मिनट तक अंतरिक्ष में रहा. उसके बाद वह समुद्र में गिर गया. अग्निकुल कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी कंपनी देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल केंद्र चलाती है. देश के बाकी सभी लॉन्च पैड इसरो चलाती है.

मोदी ने तोड़ा अपना रिकार्ड 200 से अधिक रैलियों रोड शो में हुए शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 से अधिक रैलियों और रोड शो के साथ गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी संबोधन के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान समाप्त किया। प्रधान मंत्री ने 2019 के चुनावों के दौरान स्टंप पर अपनी लगभग 145 सार्वजनिक व्यस्तताओं को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। इस बार प्रचार की अवधि 76 दिन की थी, जबकि पांच साल पहले चुनाव में यह 68 दिन थी। जब चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की, तो मोदी 15 मार्च से 17 मार्च के बीच तीन दिनों में सभी पांच राज्यों को कवर करते हुए दक्षिणी भारत के राजनीतिक दौरे पर थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश कर रही है - तीन राज्य जहां उसने 2019 में कोई सीट नहीं जीती थी - और कर्नाटक में अपनी ताकत बनाए रखने और तेलंगाना में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उनके अभियान की सफलता की सीमा 4 जून को ही पता चलेगी, जब चुनाव परिणाम घोषित होने वाले हैं। 73 साल की उम्र में, मोदी न केवल रैलियों की संख्या और उनके द्वारा तय की गई दूरी के मामले में किसी भी अन्य नेता से आगे थे.

काशी भक्ति, शक्ति और वैराग्य का शहर है- मोदी

नई दिल्ली। पीएम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी (काशी) के मतदाताओं को एक विशेष संदेश दिया, जहां मतदान होना है, और उनसे बड़ी संख्या में बाहर जाने और मतदान करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन आ गया है। मेरे लिए, काशी भक्ति, शक्ति और वैराग्य का शहर है, काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, संगीत की भूमि है। इस शहर का प्रतिनिधि बनना बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव है। देश भर में भाजपा के लिए प्रचार करने के बाद, प्रधान मंत्री मोदी ने आम चुनाव के अंतिम चरण के लिए गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में अपना चुनाव अभियान समाप्त किया। अपने वीडियो संदेश में मोदी ने कहा कि काशी का इस बार का चुनाव न केवल नवकाशी बल्कि एक विकसित भारत के निर्माण का चुनाव है। काशी के लोगों को 1 जून को एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

पाक के कब्जे वाले कश्मीर में चाईना की गतिविधि बढ़ी

नई दिल्ली. चीन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार चीनी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, चीन पाकिस्तान को स्टीलहेड बंकरों के निर्माण में सहायता कर रहा है। ड्रैगन ने उन्नत मानव रहित हवाई और लड़ाकू हवाई वाहनों के साथ पाकिस्तानी सेना की भी मदद की। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें... बुधवार को अधिकारियों ने कहा पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी चीन पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना की रक्षा क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, जिसमें स्टीलहेड बंकरों का निर्माण और मानव रहित हवाई और लड़ाकू हवाई वाहनों का प्रावधान शामिल है। चीनी सहायता अत्यधिक एन्क्रिप्टेड संचार टावरों की स्थापना और एलओसी पर भूमिगत फाइबर केबल बिछाने तक फैली हुई है। उन्होंने कहा इसके अलावा, चीनी मूल के उन्नत रडार सिस्टम, जैसे कि जेवाई और एचजीआर श्रृंखला, को मध्यम और निम्न ऊंचाई पर लक्ष्य का पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है.

कुपवाड़ा में सेना के 3 कर्नल समेत 16 पर एफआईआर

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के 16 अफसरों और जवानों के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती का मामला दर्ज किया गया है। यह केस जिन सैन्य अफसरों के खिलाफ दर्ज हुआ है, उनमें तीन लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। मंगलवार की देर रात कुपवाड़ा पुलिस थाने में हमला बोलने के आरोप में सैनिकों के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि टेरिटोरियम आर्मी के एक जवान से पुलिस ने पूछताछ की थी। इससे सेना के लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस थाने पर ही अटैक कर दिया। पुलिस का कहना है कि कथित ड्रग्स केस के आरोप में जवान से पूछताछ हो रही थी। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सेना के जवान हमले के दौरान वर्दी में थे और हथियारों से लैस थे। उनके साथ कई सीनियर अधिकारी भी थे। टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना की ही एक विंग है, जिसे रिजर्व फोर्स के तौर पर रखा जाता है। इसमें पार्ट टाइम वॉलंटियर भी शामिल होते हैं, जो सेना को ऑपरेशंस के दौरान मदद करते हैं। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सूद, राजीव चौहान और निखिल के नेतृत्व में सेना के जवाब पुलिस थाने में घुस आए।

18वीं लोकसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेगी!

हरीश गुप्ता

विपक्षी दलों ने अब मोटे तौर पर यह मान लिया है कि 18वीं लोकसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। चूंकि अब तक के सबसे लंबे और सबसे कठिन संसदीय चुनावों में मतदान समाप्त हो रहा है, इसलिए बहस सत्तारूढ़ दल को 4 जून को मिलने वाले आंकड़ों तक सीमित हो गई है। इंडी गठबंधन के शुभचिंतक कह सकते हैं कि भाजपा को 220 लोकसभा सीटों के भीतर रोका जा सकता है और तब एनडीए को पीएम नरेंद्र मोदी की जगह नया नेता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

लेकिन ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं है जो भाजपा के 350 सीटों के आंकड़े को छू लेने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चौबीसों घंटे चलने वाली टीवी बहसों के दौरान उभरे कई कारणों से सच्चाई कहीं न कहीं भाजपा की ओर झुकाव के बीच हो सकती है। ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि भाजपा की निचली सीमा 250-260 सीटों के बीच है। जबकि ऊपरी सीमा 300 सीटों के आंकड़े को छू सकती है और पूरी संभावना है कि मोदी मामूली अंतर से एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इन चुनावों में नंबर गेम से ज्यादा नजरें भाजपा उम्मीदवारों की जीत के अंतर पर भी टिकी हैं। इनमें से कुछ उम्मीदवार अतीत में कई निर्वाचन क्षेत्रों में पांच लाख से अधिक वोटों के अंतर से लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 में लगभग 200 भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर एक लाख वोटों से अधिक था। यदि भाजपा उम्मीदवारों के लिए जीत का अंतर काफी कम हो जाता है, तो मोदी के विरोधी यह कहकर खुश हो सकते हैं कि वह अब अजेय नहीं हैं। भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों के लिए भारी जीत का अंतर बनाए रखने की स्थिति में, देश में एक सख्त मोदी 3.0 कार्यकाल का उदय हो सकता है और यात्रा आगे भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी 4 जून के तुरंत बाद अपने एजेंडे को लागू करने के लिए बेताब दिख रहे हैं और अपने नए मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। वह 10 जून के आसपास शपथ लेने और उन्हें एक स्पष्ट रोड मैप देने की योजना बना रहे हैं। अपने कई साक्षात्कारों में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एक योजना तैयार करने के लिए कहा है कि पहले 100 दिनों के दौरान क्या किया जा सकता है। अगले 100 दिनों के भीतर लागू किए जाने वाले निर्णयों की एक सूची तैयार करने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिवों के 10 समूहों का अलग से गठन किया। इन विचार-विमर्श में शामिल प्रमुख मंत्रालयों में कृषि, वित्त, विदेश, रक्षा और अन्य शामिल हैं।

सरकार के आंतरिक और बाहरी एजेंडे को आकार देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न मंत्रियों और सचिवों के इनपुट एकत्र किए जा रहे हैं। मोदी के पास लगभग एक साल से लंबित चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने की चुनौती है। अधिसूचना से श्रमिकों को वेतन के मामले में मदद मिलेगी, लेकिन उन्हें एक नई 'हायर एंड फायर' व्यवस्था का भी सामना करना पड़ेगा। उनकी एक और पसंदीदा परियोजना, एक राष्ट्र एक चुनाव, को परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ नई संसद के समक्ष लाया जाने वाला है, जिससे लोकसभा सीटों को 700 से अधिक सांसदों तक बढ़ाने की योजना बनाई जा सके। यह काफी समय से लंबित है। मोदी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जनसांख्यिकीय आयोग भी स्थापित करने वाले हैं। 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 7 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर देने की योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अगर मोदी को भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरा कार्यकाल मिलता है तो अमेरिका और कनाडा निज्जर मामले में मतभेद दूर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर व्यवसाय-आधारित और अर्थव्यवस्था-चालित हैं। बदलाव का एक संकेत तब सामने आया जब एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और वैश्विक राजनीतिक जोखिम सलाहकार इयान ब्रेमर मतदान के अंतिम चरण में मोदी के पक्ष में अपनी राय लेकर सामने आए।

उन्होंने कहा, ''देश भारत के करीब आना चाहते हैं क्योंकि उसकी वैश्विक रणनीति बढ़ती जा रही है-वैश्विक दक्षिण के साथ, पश्चिम के साथ, हालांकि चीन के साथ बिल्कुल नहीं।'' इससे पहले, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टें ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर रही थीं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और मोदी 15-16 जून को इटली में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मुलाकात के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा पर विचार कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आने वाले महीनों में और भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैं। प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को यूक्रेन शांति सम्मेलन में भी भाग लेना है, जो 15-16 जून को स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में होना है, जहां जी-7 नेताओं के इटली से आने की उम्मीद है। विदेश मंत्री के 10-11 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूसी शहर निजनी नोवगोरोड की यात्रा करने की भी उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि इन सभी निमंत्रणों पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद परिणाम घोषित होने के बाद ही की जा सकती है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में अपनी टीमें तैनात की हैं, क्योंकि इन राज्यों को साइबर धोखाधड़ी कॉल के प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। हरियाणा के लोगों को ठगने वाले गिरोह के सदस्यों की पहचान करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल के दिनों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं।

बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में सियासत

विपक्ष ने सरकार को घेरा, दो परिवार मुआवजा राशि से नाखुश

बेमेतरा। बारूद फैक्ट्री में हुए बम धमाके को लेकर के नया आदेश जारी हो गया है। जिला प्रशासन ने प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया है। साथ ही तीन बॉयलर के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। वहीं इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गवाई हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे की राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कंपनी की तरफ से 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है जबकि सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन दो परिवार ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन दो लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार किया है। उनके लिए आगे क्या होगा।?

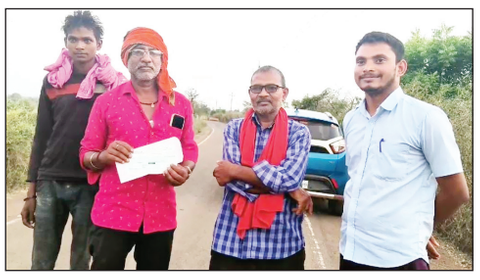

बोरसी-पिरदा के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में 25 मई को ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 8 मजदूर लापता हुए थे वहीं 1 मजदूर की मौत हो गयी थी। हादसे के बाद से लगातार मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने लापता और मृतक के परिजनों को 30-30 लाख रु देने का फैसला लिया है।राज्य शासन ने मृतक के परिजनों को 05-05 लाख रुपये देने की पहले ही घोषणा कर रखी है।मजदूर के परिजन समेत राजनीतिक दल मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। मुआवजा राशि को लेकर होकर विरोध को देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने लापता और मृतक के परिजनों को 30-30 लाख रुपये देने का घोषणा की लेकिन अब इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि दो परिवारों ने ज्यादा मुआवजा राशि की मांग करते हुए चेक लेने से इनकार कर दिया है।

पीड़ित परिजन मनहरण यदु ने कहा लापता और मृतक के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा फैक्ट्री उठाएगा। साथ ही मृतकों के पीएफ का पैसा 07 हजार उनके परिजनों के खाते में हर महीने डालने की बात फैक्टरी प्रबंधन ने मौखिक कही है।

आपको बता दें कि बुधवार की रात फैक्ट्री प्रबंधन ने 07 पीड़ित परिवारों को 29-29 लाख रुपये का चेक और 1 -1 लाख रु नगद दिया है। वही 02 पीड़ित परिवारों शंकर यादव और लोकनाथ यादव के परिजनों ने 50 लाख की मांग पर अड़े हैं।दोनों ही परिवारों ने चेक लेने से मना कर दिया है।

मीडिया जब इस्पात की जानकारी लेने का प्रयास किया तो पता चला कि जिन दो लोगों ने पैसा लेने से मना किया है वो उसरा गांव के निवासी हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं। इस वजह से इन लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया है। यह विषय भी जांच का है कि जिन लोगों ने पैसा लेने से इनकार किया है वास्तव में उनकी मांग क्या है। लेकिन जिन लोगों को पैसा दिया गया वो प्रशासन की मौजूदगी में 30 लाख रुपए छह लोगों को भुगतान कर दिया गया है। बड़ा सवाल ये भी है कि जिन लोगों को पैसा भुगतान हुआ है वह लोग अब कहां हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है।

जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर के कहा था कि हमें जो भी विस्फोट में अवशेष मिले हैं उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे और डीएनए टेस्ट के बाद ही ये बात सामने आएगी कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। हालांकि आठ लोगों के गायब होने की सूचना बताई गई थी।अब ये माना जा रहा है कि जो लोग सामने नहीं आए हैं वो विस्फोट में चल बसे हैं। आप खुद ही सोचिए कि विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा कि परिवार वालों को अस्थियां तक नहीं मिली। अब डीएनए टेस्ट से ये पता चलेगा कि उसमें कितने लोग थे।जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया है, वे अब ये मानकर चल रहे हैं कि उनके करीबी नहीं रहे।बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर है कि कल तक गायब होने की सूचना किसी और रूप में दे रहे थे और अब जान की कीमत का भुगतान किया जा रहा है।

बेमेतरा के हादसे के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना शव मिले लोगों को मुआवजा दिया जाना और अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम ने लिखा कि हम सब शर्मिंदा हैं।

बीजेपी सरकार के इस कामकाज को लेकर के भूपेश बघेल का यह ट्वीट हुआ है हालांकि बहुत सारे लोगों ने भूपेश बघेल सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपका समय में भी इस तरह के बहुत सारे काम हुए थे लेकिन कांग्रेस द्वारा मुखर होकर के इस तरह के ट्वीट करने से मुद्दा चर्चा में बना हुआ है।

जमीन विवाद : कोटवार ने पूर्व महिला सरपंच समेत दो महिलाओं को ट्रैक्टर से रौंदा

आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

तखतपुर। बिलासपुर जिले में तखतपुर तहसील से जमीन विवाद को लेकर खौफनाक मामला सामने आया है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में कोटवार ने दो आदिवासी महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत के कारण उन्हें बिलासपुर सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल महिलाओं में एक पूर्व सरपंच है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीजा का है। यहां जमीन विवाद में पूर्व सरपंच समेत दो आदिवासी महिलाओं के ऊपर कोटवार सहित चार लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाया दिया। इस घटना में दोनों महिला को गंभीर चोट आई है। घटना में घायल महिलाओं को इलाज के लिए फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। घायल महिला बाल्का कोल ग्राम पंचायत बीजा की पूर्व सरपंच है और दूसरी महिला अल्का कोल है।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कोटवार वीरेंद्र रजक, एक अपचारी समेत दो अन्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण भारी संख्या में थाने पहुंचे हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कार्रवाई में जुटी हुई है।

घायलों को सिम्स अस्पताल में नहीं मिला बेड

जमीन विवाद में घायल हुई महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी सिम्स अस्पताल में लगाया गया। लेकिन घायलों को अस्पताल में बेड नहीं मिला। जिसके लिए तीन घंटे से सिम्स अस्पताल में परिजन स्ट्रेचर पर पीड़ितों को लेकर भटकते रहे हैं। ऐसी व्यवस्था से नाराज परिजनों ने सिम्स प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई है और घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए हैं। ऐसी लचर व्यवस्था ने सिम्स अस्पताल में बेहतर इलाज व अन्य दावों की पोल खोल दी है।

आरएसएस ने नारद जयंती पर किया संगोष्ठी का आयोजन, पत्रकारों का हुआ सम्मान

कोरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरिया के प्रचार विभाग द्वारा नारद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए साथ ही पत्रकारों का सम्मान किया गया। नारद जयंती पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह संघ चालक नरेश सोनी,वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बड़ेरिया,उत्तम कश्यप एवं जिला प्रचार प्रमुख शैलेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

नारद जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया,जिसके बाद उद्बोधन की श्रृंखला में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बड़ेरिया ने कहा कि विश्व के प्रथम पत्रकार नारद जी रहे वह लोक मंगल की कामना को लेकर चले थे,आज के दौर में भी पत्रकारों को लोक मंगल की कामना को लेकर चलना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार उत्तम कश्यप ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में नारद जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, नारदजी की पत्रकारिता पर देव और दानव दोनो विश्वास करते थे। उन्हें रनवास तक जाने की इजाजत थी, जनमानस में सही सूचना पहुंचाना नारद का दायित्व है। हिंदू संस्कृति में देवऋषि नारद मुनि जी का एक विशिष्ट चरित्र एवं स्थान है। देवर्षि नारद मुनि जी के हर परामर्श में और प्रत्येक वक्तव्य में लोकहित झलकता है।

आरएसएस के जिला सह संघ चालक नरेश सोनी ने कहा कि नारद के रूप में ढलकर ही पत्रकारिता किया जा सकता है,उनके चरित्र को नकारात्मक ना मानकर पत्रकारों को काम करना चाहिए। खबरें वही देनी चाहिए जो समाज के लिए लाभप्रद हो। उन्होंने कहा कि नारद जी पत्रकारिता के आदर्श हैं। वह झगड़ा भी सिर्फ सच बोलने के लिए करते थे। आज के दौर में पत्रकारिता को सच पर ही आधारित होना चाहिए। जो लोग अपनी विरासत और अपने इतिहास को याद रखते हैं इतिहास भी उन्हे हमेशा याद रखता है। उन्होंने कहा कि समाज में पत्रकारों का भय बना रहना चाहिए तभी लोग गलत काम करने से रुकेंगे। उन्होंने कहा कि लोग पत्रकारों से समाज बहुत अपेक्षाएं रखता है पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सकारात्मक दृष्टि से जन की बातों को प्रशासन तक और प्रशासन की बातों को जन तक पहुचाएं। निष्कपट और निश्चल भाव से यह काम होना चाहिए।

पत्रकार संवर्त कुमार रूप ने नारद जी पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता में लकीर के फकीर न बनें किसी लोभ लालच में अधिकांशतः सच कहने वाले पत्रकार नही हैं,वर्तमान में सच्ची पत्रकारिता दुर्लभ होती जा रही है।पत्रकारों को जनहित की पत्रकारिता को प्रेरित रहना होगा। साथ ही निष्पक्ष संवाद का आदान प्रदान ही होना आवश्यक है। अगर पत्रकार नही रहे तो जीवन सुना है। सूचनाएं नही रही तो सब कुछ अधूरा है।

सूखने की कगार पर गंगरेल बांध, दो टीएमसी रह गया पानी

धमतरी। धमतरी जिले में गंगरेल बांध है, जहां लोग दूर-दूर से घूमने आते हैं। यह बांध करीब 12 से 13 साल बाद सूखे की मार झेल रहा है। 32.5 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध सूखने के कगार पर है। वर्तमान में अब महज दो टीएमसी उपयोगी पानी शेष रह गया है, जो कुल क्षमता से मात्र 8 प्रतिशत ही है। इस बार मानसून समय पर दस्तक नहीं देता है और अच्छी वर्षा नहीं होती है तो इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। साथ ही पेयजल जलापूर्ति में कटौती की जाएगी।

गंगरेल बांध से राजधानी समेत आसपास के कई जिलों को इस बांध से पानी दिया जाता है। भविष्य में यदि अच्छी वर्षा नहीं होती है तो इन जिलों की भी परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने गंगरेल बांध में करीब 28.31 अरब लीटर पानी है, जो महज 80 दिन का पानी है। यही वजह है कि अब गंगरेल बांध प्रबंधन बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट को पानी देना बंद कर दिया है।

गंगरेल बांध इस साल गर्मी में सूखे की मार झेल रहा है। बांध से करीब 900 तालाबों को पहले ही भरा जा चुका है। गंगरेल को खाली देखकर जिला प्रशासन ने पहली बार जल जगार उत्सव मना रहा है। जल जगार कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय भूमि जल आयोग की टीम ने भी गंगरेल बांध की स्थति को लेकर चिंता जाहिर की है और जल संरक्षण की ओर धमतरी सहित प्रदेशवासियों को जागरूक होने अपील की है।

स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में बीते 25 मई की सुबह करीब 7.50 बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट हो गया था। यह फैक्टरी बेरला थाना अंतर्गत पुलिस चौकी कंडरका क्षेत्र के ग्राम पिरदा (बोरसी) में है। घटना में एक की मौत और 8 घायल हुए हैं। घायलों का उपचार रायपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस बीच कंडरका पुलिस ने 29 मई की देर शाम सात बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हादसे के बाद लगातार एफआईआर की मांग की जा रहीं थी।

जानकारी अनुसार 25 मई की सुबह 7:50 बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी पिरदा के पीईटीएन सेक्शन में तेज ब्लास्ट होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल के पास मानव अंग के अंश प्राप्त होने से मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस बल के सहयोग से घटना के बाद घटना मे आहत हुए लोगों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया था।

इसमें एक व्यक्ति सेवक राम साहू (50) पुत्र डहर साहू निवासी ग्राम पिरदा पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला की मौत हो गई थी। इसके अलावा पीईटीएन सेक्शन मे कार्यरत आठ मजदूर घटना के बाद से लापता होने की सूचना पर गुम इंसान दर्ज किया गया है। उप मुख्य विस्फोटक निरीक्षक पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक्सप्लोसिव सुरक्षा संगठन केन्द्रीय संचिवालय भवन अटल नगर रायपुर की रिपोर्ट एवं मर्ग जांच मे आये तथ्य से स्पेशल ब्लास्ट कंपनी पिरदा के पदाधिकारी अवधेश जैन व अन्य की विस्फोटक पदार्थ के रख रखाव, नियमों का उल्लंघन, लापरवाही बरतने के कारण घटना घटित होना प्रदर्शित हुआ है।

स्पेशल ब्लास्ट कंपनी पिरदा के पदाधिकारी अवधेश जैन व अन्य द्वारा धारा 286,337,304,(ए) भादवि धारा 9 क्ष 9 ष्ट विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

निर्माणाधीन इमारत का स्ट्रक्चर नीचे गिरा, 13 मजदूर दबे

दुर्ग। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी के चिखली गांव में निर्माणाधीन क्लब हाउस का 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर भरभरा कर नीचे गिर गया। जिसके नीचे 13 मजदूर नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दबे मजदूरों को बाहर निकला गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और निजी अस्पताल लेकर जाया गया। सभी मजदूरों को हल्की गंभीर चोटें आई हैं, सभी मजदूरों को हालत सामान्य बताई जा रही है। पूरी घटना चिखली गांव के शिवनाथ नदी से सटे बाफना गोल्फ क्लब की है। जहां 27 फीट ऊंचा क्लब हाउस का स्ट्रक्चर भरभराकर नीचे गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूरों की गंभीर चोटें आई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में नौ पुरुष और चार महिलाएं शामिल है जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूरों को हालत सामान्य बताया जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला।

एसपी ने थाना प्रभारी और आरक्षकों का किया फेरबदल

सक्ति। सक्ति जिले की एसपी अंकिता शर्मा ने बेहतर पुलिसिंग को लेकर बड़ा फेर बदल किया गया है। हसौद थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुजूर को रक्षित केंद्र और सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र शुक्ला को रक्षित केंद्र भेजा गया है। वहीं, विन्टन साहू को हसौद थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, दो प्र. आरक्षक मोहित देवांगन बेच नंबर 402, राजेंद्र यादव बेच नंबर 350 को रक्षित केंद्र से डभरा थाना में पदस्थ किया गया है। सक्ति थाने में पदस्थ प्र. आरक्षक अजय प्रताप कुर्रे बेच नंबर 13 और आरक्षक मनोज लहरे बेच नंबर 192 दोनो को रक्षित केंद्र भेजा गया है। इस तरह से निरीक्षक, प्र. आरक्षक, आरक्षक के पदस्थापना में फेरबदल किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश आने तक अस्थायी रूप से जारी किया गया है।

तालाब में मिला चार क्विंटल महुआ लहान

सक्ती। ग्राम चारपारा में अवैध रूप से शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने एसडीओपी के नेतृत्व में दबिश दी मगर पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। घर में ना शराब मिला और ना ग्रामीण मिले लेकिन तालाब में शराब बनाने के लिए डूबाकर रखे गए महुआ लहान को पुलिस ने नष्ट किया है। मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम चारपारा में अवैध रूप से अवैध रूप से शराब बनाने एवं बिक्री करने की सूचना पर एसडीओपी सक्ती मनीष कुंवर, थाना प्रभारी डभरा प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक चंद्रहास सिन्हा, चौकी प्रभारी अडभार कमल मेरिशा और थाना मालखरौदा के पुलिस टीम तैयार कर ग्राम चारपारा में दबिश दी। पुलिस के आने की सूचना शराब बनाने वालों को पहले ही मिल गई थी इसलिए घर में ना शराब मिला और ना ही बनाने वाले मिले। लेकिन महुआ शराब बनाने के लिए गांव के तालाब में डूबाए गए महुआ लहान करीब चार क्विंटल को निकाल कर नष्ट किया गया।

नशे में धुत युवकों ने पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी

बिलासपुर। नशे में धुत युवकों ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और जमकर विवाद किया। यह घटना बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवर व्यू की है। पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो शराब के नशे में बाइक सवार तीन युवकों ने हुज्जतबाजी कर हंगामा मचाया। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक, बीती रात कोतवाली टीआई विजय चौधरी स्टाफ के साथ रिवर व्यू रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान सरकंडा के पुराना पुल से शनिचरी की ओर जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को आरक्षक नरेश निराला ने रुकवाया। तीनों युवक शराब के नशे में थे। युवक आरक्षक को अकेले देखकर उसके साथ गुंडागर्दी करते हुए गाली गलौज करने लगे। आरक्षक ने गाली देने से मना किया तो तीनों ने उसके साथ हुज्जतबाजी करते हुए वर्दी फाड़ दी। आरक्षक के आवाज लगाने पर दूर में खड़े टीआई चौधरी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों युवकों को पकड़कर थाने ले गए।

कार ने बाइक को मारी टक्कर थम नहीं रहे हादसे

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के लालबाग में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मार्ग में तीन बड़े हादसे हो चुके हैं, जहां एक ने तो अपनी जान ही गवां दी है। फिर भी इस मार्ग में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं इस माह में तो कुछ दिनों पहले एक तेज रफ्तार कार चालक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में बाइक के जहां 2 टुकड़े हो गए थे, वहीं बाइक सवार को गंभीर चोट आने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, दूसरी घटना एक तेज रफ्तार टिप्पर चालक ने रफ्तार पूर्वक चलाते हुए एक स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, तीसरी घटना फिर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार चालक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद बाइक सवार को चोट आई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

तालाब को गहरा करके बना दिया खदान विरोध के बाद अफसरों ने रुकवाया काम

दुर्ग। उतई नगर पंचायत क्षेत्र में शीतला तालाब गहरीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहा विवाद कुछ समय के लिए थम गया है।तालाब के गहरीकरण के काम को रुकवाने के लिए महिलाएं लामबंद हुईं।महिलाओं ने पहले पंचायत भवन का घेराव किया।फिर पैदल मार्च करते हुए शीतला तालाब को घेर लिया।इसके बाद उतई थाना पुलिस अफसरों का दल तालाब के पास पहुंचा।जिन्हें महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई।

महिलाओं का कहना है कि तालाब की खुदाई बंद कराने के लिए ना तो पार्षद सुन रहे हैं और ना ही अध्यक्ष। तालाब खुदाई के कारण अब खदान बन चुकी है।जिससे कारण कई तरह का खतरा पैदा हो चुका है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष समेत सभी वार्डों के पार्षदों ने मिलकर तालाब खोदने की अनुमति दे दी।

ग्रामवासी रजनी ने कहाजो ठेकेदार तालाब खोद रहा है उसे तालाब गहरीकरण की कोई समझ नहीं है। अब ये तालाब खदान के रूप में बदल चुका है। जिसके कारण कई तरह की दुर्घटनाओं हो सकती है।

अब विरोध के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों के मुताबिक तालाब को समतल करने की बात कही। तालाब की अव्यवस्थित खुदाई और तालाब के भीतर अनेक जगहों पर गहरे खाई नुमा गड्ढे खोदे जाने से तालाब बर्बाद हो चुका है। तालाब में पानी भर भी दिया जाय तो निस्तारी करने वालों की जान को हमेशा खतरा बना रहेगा।कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

आरटीआई कार्यकर्ता व्यर्थ बैठ कर अपना और हमारा समय खराब न करें

धमतरी। जिले के जल संसाधन विभाग यदि आप कभी जाए तो ऑफिस की हर दीवार, हर आलमारी और हर दरवाजे पर एक सूचना लिखे होने का पोस्टर नजर आएगा। उस पोस्टर में लिखा हुआ है, आरटीआई कार्यकर्ता व्यर्थ बैठ कर अपना और हमारा समय खराब न करें। इस पोस्टर लगाने का मकसद जानने मीडिया खुद ऑफिस पहुंचा और वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से इसकी जानकारी ली।

आरटीआई कार्यकर्ताओं से परेशान विभाग के कर्मचारी

इन पोस्टर्स के बारे में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला निकला। पता चला कि जल संसाधन विभाग के दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी आरटीआई लगाने वालों से इतने परेशान हो गए हैं कि इसके लिए एक बाकायदा आदेश जारी किया गया और इस तरह की सूचना हर दीवार पर लगाई गई। यहां के वरिष्ठ कर्मचारी बताते है कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता सिर्फ परेशान करने के इरादे से आते हैं। ऐसे लोगों के कारण कामकाज प्रभावित होता है। इस कारण ये कदम उठाना पड़ा।

जानकारी लेने के बाद भी ऑफिस में डटे रहते हैं आरटीआई कार्यकर्ता

जल संसाधन विभाग के इंजीनियर गोपाल शर्मा ने बताया कि बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता जानकारी लेने के बाद भी बैठे रहते हैं। उससे शासकीय काम पूरी तरह प्रभावित होता है। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का काम भी प्रभावित होता है। अगर उन्हें अटेंड नहीं करते हैं तो नाराजगी दिखाते हैं। इसी कारण अधिकारियों के निर्देश पर पोस्टर को ऑफिस में लगाया गया है।

गोपाल शर्मा ने आगे कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अपनी जानकारी लें और ऑफिस से चले जाए, इस उद्देश्य से पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ आरटीआई कार्यकर्ता लगातार जानकारी ले रहे हैं। लेकिन वह जनहित में कहीं भी दिखाई नहीं देता। बहुत सारी पुरानी पुरानी जानकारियां मांगी जाती है लेकिन ऑफिस काफी पुराना है। साल 1972 से ऑफिस संचालित है। कई जानकारियां को दीमक खा गई है। कई जानकारियां सबडिवीजन ट्रांसफर हो गए हैं। परेशान करने के उद्देश्य से ही कई आरटीआई कार्यकर्ता दफ्तर में पहुंचते हैं।

पोस्टर लगने के बाद जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को राहत

पिछले 4 महीने से जलसंसाधन विभाग के ऑफिस में ये तख्तियां या पोस्टर दिखने लगे हैं। विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पोस्टर लगाने के बाद आरटीआई कार्यकर्ताओं के लगातार दफ्तर पहुंचने में कुछ कमी आई है। यदि कोई आ भी रहा है तो वह जानकारी लेकर चले जा रहा है। जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है।

संक्षिप्त समाचार

बेबीलोन होटल मालिक ने अवैध कब्जे पर बनवाया था किचन शेड, चला बुलडोजर

रायपुर। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित

बेबीलोन होटल के अवैध कब्जे पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। होटल मालिक ने होटल के पीछे नाले में 15 बाई 300 वर्गफीट के अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 51 के क्षेत्र में वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलान के पीछे के बड़े नाले पर अवैध कब्जा कर रखा था। होटल के मालिक ने उसमें किचन शेड लगभग 15 बाई 300 वर्गफीट क्षेत्र में बनाकर रखा था। नगर निगम ने इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। नाले पर कब्जा जमाये कब्जाधारी ने नाले का कब्जा को तीन दिन के भीतर हटाने की बात कही है। इस पर जोन कमिश्नर ने इसकी जानकारी आयुक्त को दी। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सम्बंधित कब्जाधारी को नाले पर किया गया। अवैध कब्जा स्वत: के व्यय और संसाधन से हटाने तीन दिनों का समय दिया गया है। जोन कमिश्नर ने बताया कि तय समयसीमा के भीतर कब्जाधारी ने कब्जा नहीं हटाया, तो नगर निगम कार्रवाई करेगी।

शिव महापुराण सुनने जा रहे श्रद्धालु हीट वेव का हो रहे शिकार, एक की मौत

रायपुर। भीषण गर्मी से भी भक्तों की आस्था

नहीं डगमगा रही है। शिव के धाम अमलेश्वर में चल रही शिव महापुराण कथा सुनने वाले सुबह से ही अपनी जगह बनाने के लिए कथा स्थल पहुंच जाते हैं लेकिन कथा का समय है ठीक दोपहर 1 से 4 बजे और नौतपा का असर रौद्र रूप दिखा रहा है ऐसे में अधिकांश बुजुर्ग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हालांकि कथा स्थल पर कूलर व पानी की व्यवस्था की गई है पर भीड़ इतनी अधिक है कि संभाल पाना मुश्किल हो रहा है,धरसीवा के 70 वर्षीय तीरथ राम साहू की मौत हो जाने के बाद व्यवस्था को और माकूल करने आयोजक हरकत में आए। जानकारी के अनुसार अमलेश्वर के कथा स्थल पर कथा सुनने धरसीवा के 70 वर्षी तीरथ राम साहू पहुंचे थे। तीरथ राम साहू को अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़े उसके साथ जो परिजन थे वह उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र अमलेश्वर ले गये,जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमलेश्वर में कथा स्थल के बाजू में ही बने अस्थाई हेल्थ कैंप में कई लोग इलाज करा रहे है। बता दें अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण कथा स्थल अमलेश्वर में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर कथा सुनने आए कई श्रोता दस्त सहित डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। वहीं बुजुर्ग लोगों को बीपी की समस्या भी आ रही है।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर रेल्वे स्टेशन में नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी आज

रायपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल भाठागांव और रेल्वे स्टेशन रायपुर के मुख्य प्रवेश द्वार क्रमांक-दो में 31 मई को एक दिन के लिए नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य देखा जा सकता है। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। रेल्वे स्टेशन में आयोजित नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक राजेश मूणत, अपर कलेक्टर श्रीमती निधि साहू, डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर राकेश सिंह, स्टेशन डायरेक्टर एन.के.साहू और रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी करेंगी। इसी तरह अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ विधायक मोतीलाल साहू और नगर निगम के उपायुक्त विनोद पाण्डे करेंगे। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति का सन्देश देने के लिए रंगीन चित्रों तथा पोस्टर्स के माध्यम से तम्बाकू के अलावा गुड़ाखू, बीड़ी, सिगरेट और शराब आदि नशीली चीजों से स्वास्थ्य को होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सचेत किया जाएगा।

राजधानी के टिंबर मील में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भारी मात्रा में लकड़ियां खाक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में गुरुवार की सुबह भनपुरी स्थित टिंबर मील में भीषण आग लग गई। लकड़ी के दरवाजे बनाने वाली फैक्ट्री में धूप में रखे लकड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतने तेजी से फैली कि सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बता दें, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची खमतराई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है। वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ रहे तापमान और भीषण गर्मी के चलते लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं।

कलेक्टर गौरव सिंह ने बाढ़ से बचाव के लिए की तैयारियों की समीक्षा बैठक मे कहा-

अनुविभागीय अधिकारी स्वयं गांव का दौरा कर बनाएं कार्ययोजना

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह जिले में बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर मानसून आने की संभावना है। जिले की सभी तहसीलों और नगर निगम में बाढ़ के संभावित स्थानों को चिन्हित करें। सभी एसडीएम अपने राजस्व अमलों के साथ स्वयं तहसीलों का दौरा करें और ग्रामीणों से चर्चा कर आपदा राहत की कार्ययोजना बनाएं। गांव-नदीतट और में गोताखोरों की तैनाती रखें। साथ ही गांवों में कुछ युवाओं के समूहो को प्रशिक्षित करें जिससे वे बाढ़ जैसी आपदा का सामना करनें में सहयोग कर सकें।

डॉ सिंह ने कहा कि बाढ़ से प्रभावितों के अभी से सुरक्षित स्थान ऐसे स्थल को चिन्हांकित करले और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से सबसे अधिक मवेशी प्रभावित होते हैं। उनके लिए भी सुरक्षित स्थान रखें। साथ ही पशुओं को होने वाले संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए दवाईयों का इंतजाम कर लें। खाद्य विभाग उचित मूल्य की दुकानों में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करें और यह भी जायजा लें कि बाजार में चना, चावल,

आटा, गुड, दाल, नमक आदि खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ताकि आवश्यकता एवं समयानुसार उपलब्धता में विलंब ना हो। संभावित बाढ़ राहत सामग्रियों के पैकेट तैयार करने हेतु टीमों का गठन भी कर लिया जाए।

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि पीएचई जिले में टंकी के सफाई के लिए विशेष अभियान चलाएं और टंकी के सफाई के बाद उस पर सफाई की तिथि वर्णित करें। बाढ़ प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्थ पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। पेयजल की गुणवत्ता शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए। एवं बाढ़ प्रभावित पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण पीएचई के माध्यम से समय पर सुनिश्चित कर लिया जाए। चिकित्या विभाग अभी से बारिश के समय फैलने वाली महामारी जैसे डायरिया, मलेरिया, पीलिया आदि के लिए दवाईयों तथा टेस्ट किट इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में कर लें। ताकि उस समय किसी प्रकार परेशानी का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि बाढ़ से पूर्व जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से ब्लॉक, तहसीलों, गांवों को जोडने वाली सड़कों की मरम्मत करा ली जाए। पुल-पुलिया की भी मरम्मत करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाए।

नगर निगम कमिश्नर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि निगम के निचली बस्तियों और कुछ विशेष स्थानों मे जो बाढ़ के स्थिति निर्मित होने की संभावना रहती है। इन जगहों पर साफ-सफाई की व्यवस्था कर ली जाए। ताकि पानी का जमाव ना हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम को अलर्ट करें। उन्होंने बताया कि शहर के सभी प्रमुख नालों की सफाई तेजी से की जा रही है, ताकि डैनेज सिस्टम दुरूस्त रहें और बारिश के दौरान पानी का जमाव ना हो। नगर निगम को सारे जोन और स्वास्थ्य विभाग की टीम संभावित बीमारियों के रोकथाम के लिए कार्य करेंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप, सभी एडीएम एवं एसडीएम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बढ़ती गर्मी में आवश्यक सावधानी बरतें : साय

रायपुर। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही है। श्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं। जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकले, धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें, पानी अधिक मात्रा में पियें, अधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस घोल पियें, छायादार जगहों पर रहें, लू लगने या तबियत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं। क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक हीटवेव के जारी रहने की बात कही है। जिसके चलते सीएम साय ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

शहर में लूट व चैन स्नैचिंग के बढ़ते मामले चिंतनीय : हरख

■ ऑटो वालों का भी वेरिफिकेशन किया जाना आवश्यक

रायपुर। शहर में संचालित हो रहे ऑटो में सवारी करने वालों के साथ लगातार हो रही लूट व चैन स्नैचिंग के मामलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब तो वे ऑटो में सवारी करने से भी डरने लगे हैं लेकिन क्या करें शहरी सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का यही तो एकमात्र माध्यम हैं। सराफा, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स जैसे मुख्य बाजार व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक आने-जाने के लिए उपभोक्ता वर्ग ऑटो का ही उपयोग करते हैं। जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किये जाने के बाद भी घटनाओं में कमी न आना और इनके न पकड़े जाने का कारण तो ऐसा लगता है कि कोई गेंग सुनियोजित तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय है।

लूट एवं चैन स्नैचिंग पर चिंता जाहिर करते हुए रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने कहा है कि पचपेड़ी नाका एवं फाफाडीह चौक जैसे बड़े चौराहों से इस प्रकार के आपराधिक तत्व ऑटो में सवार होकर शहर के विभिन्न जगहों में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं,यह बात पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों को दी गई थी किंतु अभी तक

इस प्रकार की घटनाओं में शामिल आरोपित नहीं पकड़े गए हैं। कुछ एक घटनाओं के पकड़े भी गए कि दूसरी घटना हो जाती है।

लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे शहर में महिला-पुरुष सदस्यों के कुछ गेंग सक्रिय है जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। प्रत्येक ऑटो वालों का भी वेरिफिकेशन किया जाना अति आवश्यक है,ऑटो की आड़ में भी इस प्रकार के गेंग अपना काम कर जाते है । शहर ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। व्यापारिक कामकाज से भी व्यापारी व उनके प्रतिनिधियों का रोजाना बाहर शहरों से आना जाना होता है। यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही ना होना अत- जिला एवं पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की लगातार हो रही घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए एक विशेष टीम का गठन करें और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करें।

वीर सावरकर को पढ़ लो, दूर हो जाएगा डिप्रेशन : पेंडसे

रायपुर। गोलियां खाकर डिप्रेशन दूर करने वाले एक बार सावरकर को पढ़ लें, तो उनकी डिप्रेशन की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। स्वतंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के जीवन में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक होते चली गईं जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। लगातार विफलताओं और नकारात्मक परिणामों के बावजूद सावरकर न कभी निराश हुए और न ही अपने लक्ष्य से भटके। उनके अटूट आत्मबल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, लेखन कौशल, सहनशीलता, बुद्धिमता और वाकपटुता से उनके समीपस्थ लोग ही उनसे प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनके विचारों के आलोचकों से लेकर ब्रिटिश शासन के अधिकारी भी उनकी अनदेखी नहीं कर पाते थे। वीर सावरकर जयंती पर उक्ताशय के विचार प्रफुल्ल पेंडसे ने व्यक्त किए।

महाराष्ट्र मंडल में सावरकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष अजय काले के अध्यक्षीय संबोधन के बाद मुख्य वक्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रफुल्ल पेंडसे ने कहा कि वीर सावरकर को पता था कि कौन सी घटना का प्रभाव कब तक और कितनी देर तक रहेगा। वर्ष 1905 में विदेशी कपड़ों की बड़े पैमाने पर होली जलाने की रूपरेखा उन्होंने लोकमान्य गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरित होकर बनाई थी। यह घटना कितनी व्यापक थी कि इसस उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 3.5 करोड़ पॉन्ड का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर बाजारों विदेशी कपड़ों की बिक्री भी बंद हो गई थी।

सावरकर पर लगभग 80 मिनट धाराप्रवाह बोलते हुए पेंडसे ने कहा कि जो कर (हाथ) सवार दे, वही सावरकर होता है। दुनिया में वीर सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें दो विभिन्न प्रकरणों में 25- 25 साल के कैद की सजा हुई थी। इसके लिए उन्हें अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल ले जाया गया। जहां के जेलर आइरिश नागरिकता वाले डेविड बेरी से उनका सामना हुआ। डेविड से चर्चा में सावरकर ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे 25- 25 साल के कैद में रहने तक भारत देश में ब्रिटिश सरकार बनी रहेगी।

अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक ढिल्लन की रिमांड बढ़ी

कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेजा जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आज कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बता दें कि आज ही चारों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हुई थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने फिर 14 की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी बताया था। पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया। ईडी ने मई महीने में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के जरिए कमाया, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया।

ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे। इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की ओर से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। अब श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। इसमें अकुशल 'अ' श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपये, 'ब' वर्ग के लिए 10,640 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 10,380 रुपये निर्धारित की गई है।

अर्द्धकुशल 'अ' वर्ग के लिए 11,550 रुपये, 'ब' वर्ग के लिए 11,290 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 11,030 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल 'अ' वर्ग के लिए 12,330 रुपये, 'ब' के लिए 12,070 रुपये और 'स' के लिए 11,810 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल 'अ' वर्ग के लिए 13,110 रुपये, 'ब' के लिए 12,850 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 12,590 रुपये किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपये प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उपादान भुगतान को लेकर फेडरेशन आफ एजुकेशन सोसायटी की हुई बैठक

रायपुर। उपादान भुगतान को लेकर फेडरेशन आफ एजुकेशन सोसायटी की बैठक राजधानी रायपुर में हुई। जिसमें कार्यरत्त सभी जिलों से प्रतिनिधि शामिल हुए। बाल आश्रम समिति के सभागार में हुई बैठक में प्रतिनिधियों को श्री अजय तिवारी व डा.सुरेश शुक्ला नीतिगत विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

जैसे कि बैठक में अवगत कराया गया प्रदेश के शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों से दिनांक 03.04.1997 से 31.03.2013 तक के अवधि में सेवा निवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के उपादान का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2024 के द्वारा विद्यालय प्रबंधकों को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है, जबकि वेतनों का सदाय अधिनियम

क्रमांक 20 सन् 1978 की धारा 5(2) के तहत् अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों व प्रबंधकीय अंशदान भुगतान के लिए होने वाले व्यय भार को संस्थागत निधि बैंक खाते मे अग्रिम में जमा करने का प्रावधान किया गया है अर्थात् शासन को भुगतान करना है, दिनांक 01.94.2013 से राज्य शासन के द्वारा ही उपादान का भुगतान भी किया जा रहा है।

प्रदेश के शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों के संचालन समितियों के अध्यक्ष/ सचिव प्रतिनिधि बुधवार की बैठक में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, चांपा जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, एमसीली, कोरबा इत्यादि जिलों से सैकड़ों प्रबंधकों के माननीय न्यायालय बिलासपुर के डी. बी. के निर्णय को अनुदान अधिनियम व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व ग्वालियर बेंच के डी. बी. निर्णय के विरुद्ध मानते हुए सर्व-सम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय में यथा शीघ्रवाद दायर करने के साथ ही स्टे प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

4 जून मतगणना को तैयार कांकेर, 18 राउंड में काउंटिंग

■ दोपहर बाद स्पष्ट रुझान की उम्मीद

कांकेर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुए मतदान की गिनती की तैयारी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। 4 जून को कांकेर लोकसभा के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर व कांकेर विधानसभा में पड़े वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज नाथिया, नवागांव कांकेर में होगी। काउंटिंग के लिए रूपरेखा भी तैयार की है।

कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया तीनों विधानसभा में अलग-अलग राउंड में गिनती की जाएगी। जिसमें हर राउंड के बाद रेंडम दो ईवीएम मशीन की गिनती ऑब्जर्वर द्वारा की जाएगी ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो रही तो वह चेक हो जाए और परिणाम सही आए। इसके अलावा गणना पूरी होने के बाद हर विधानसभा में रेंडम पांच मशीनों के

वीवीपैट की भी गिनती कर उसका गणना से मिलान किया जाएगा।

लोकसभा के नतीजे के लिए चार जिलों के आठ विधानसभा में काउंटिंग की जाएगी। जिसमें कांकेर जिले के 3 विधानसभा के अलावा धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा की गिनती भोपाल राव पवार पॉलीटेक्निक कॉलेज रूद्री, बालोद जिले के संजारी बालोद, डौंडी लोहारा व गुंडरदेही विधानसभा की गिनती लाइवलीहुड कॉलेज पाकुरभाट, बालोद और कोंडगांव जिले के केशकाल विधानसभा की गिनती गुंडाधुर स्नातकोत्तर कॉलेज कोंडागांव में होगी।

सुबह 7 बजे ईवीएम मशीन का स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा। कोंडागांव, धमतरी व बालोद में सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीन से गिनती शुरू हो जाएगी। जबकि कांकेर में इसके आधे घंटे बाद से सुबह 8.30 मिनट पर ईवीएम मशीन से गिनती शुरू होगी।

कांकेर में 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। कांकेर में तीन विधानसभा की होने वाली गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाए हैं। जिसमें अंतागढ़ विधानसभा में 16 राउंड में, भानुप्रतापपुर विधानसभा में 19 राउंड में और कांकेर विधानसभा में 18 राउंड में वोटों की गिनती पूरी होगी।

कांकेर लोकसभा के लिए अब तक 26 मई की स्थिति में 8 विधानसभा से कुल 6326 डाक मतपत्र व ईटीपी बीएस प्राप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में 1217 डाक मतपत्र मिले हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में 136 डाक मतपत्र मिले हैं। कांकेर जिले के कांकेर विधानसभा में 681 और भानुप्रतापपुर में 636 डाक मतपत्र मिले हैं। बालोद जिले के विधानसभा संजारी बालोद में 258, डोंडीलोहारा में 210 और गुंडरदेही में 186 के अलावा कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा में 308 डाक मतपत्र मिले हैं। डाक मतपत्रों के आने का सिलसिला अभी जारी है।

मतगणना केंद्र में किसी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने तीन लेयर की सुरक्षा घेराबंदी की गई है। पहले घेरे में जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके बाद दूसरे घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और तीसरे घेरे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात होंगे। गणना स्थल के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ वासियों को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, प्रदेश में जल्द बरसेंगे बादल

रायपुर। देशभर में गुरुवार को नौतपा का पांचवा दिन था। छत्तीसगढ़ में बुधवार का तापमान 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में लू की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसी बीच प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेशवासियों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारत में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही बारिश के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के अनुसार, इस साल समय से 2 दिन पहले ही मानसून केरल के रास्ते भारत पहुंच चुका है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 तारीख तक मानसून दस्तक देगा।

इससे पहले मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था, कि देश के मानसून की 31 मई से हो सकती है। केरल में मानसून के दस्तक देते ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी। लेकिन मानसून ने 2 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है, इसलिए प्रदेश में भी दो दिन पहले ही बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस बार पिछले से अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है। यह मानसून किसानों के लिए काफी बेहतर हो सकता है। 106 फीसदी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। बुधवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43 सो 45 डिग्री दर्ज की गई। वहीं रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा। रायगढ़ में लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तर्ज किया गया।

विपक्ष का ब्रह्मास्त्र कैसे बन गया मोदी का चुनावी हथियार

अभिनय आकाश

लोकसभा चुनाव से पहले के महीनों में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह था कि भारतीय संविधान खतरे में है और महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी नेताओं ने मतदाताओं को बताया कि उन्हें संविधान बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक को वोट क्यों देना चाहिए। लेकिन सात चरण के आम चुनाव के आधे समय के दौरान, पीएम मोदी ने विपक्ष के हथियार का इस्तेमाल करते हुए पासा पलट दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे वास्तव में संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा को वोट देना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष का ब्रह्मास्त्र कैसे पलट दिया? अप्रैल के अंत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र, आरक्षण, संविधान और गरीबों के अधिकारों को बचाने का चुनाव है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था 400 पार (400+ सीटें)। क्या वह अब 400 पार कह रहे हैं? अब वह 150 पार करने की भी बात नहीं कर रहे हैं। बयान आ रहे हैं कि हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि देश की जनता असली बात समझ गई है। देश की जनता समझ गई है कि ये लोग संविधान और गरीबों के अधिकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन, इसके साथ ही, भाजपा ने कर्नाटक में एक विवाद को जन्म दिया, जो इस बात का आधार बनेगा कि पार्टी आने वाले दिनों में अपने तर्कों का उपयोग करके विपक्ष पर कैसे पलटवार करेगी। पीएम ने एक नई पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया कि कैसे कर्नाटक में मुसलमानों को संविधान के लोकाचार के खिलाफ आरक्षण दिया जा रहा है और जो इसके हकदार हैं उन्हें लूटा जा रहा है। लगभग उसी समय, जब गांधी भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे, मोदी ने तेलंगाना के मेडल जिले में एक रैली में हमला बोलते हुए कहा कि वे (कांग्रेस) अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं उन्हें धर्म के नाम पर मुसलमानों को दलितों, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मिलने वाला आरक्षण नहीं देने दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि यह वही रैली थी जिसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि वह अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न भव्य तरीके से मनाएंगे, और इस प्रकार संविधान को बचाने पर प्रति-कथा का पुनर्निर्माण करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस धर्म-आधारित आरक्षण के समर्थक हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आनुपातिक आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की भी मांग की। तो इससे पता चलता है कि वे ही लोग हैं जो आरक्षण बदलने के इच्छुक हैं। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक आदेश तब आया जब मतदान के दो चरण बचे थे, जिससे भारतीय गुट पूरी तरह असहज हो गया। आदेश में 2010 से पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत कई वर्गों को जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी तुष्टीकरण का एक पहलू था जिसे भाजपा ने अनदेखा और अप्रयुक्त नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी जातियों की राज्य सूची में 179 जातियाँ हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष हंसराज अहीर के अनुसार, 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तत्काल प्रतिक्रिया से भाजपा को अपना आक्रोश बढ़ाने में मदद मिली, जहां उन्होंने कहा कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं अदालतों का सम्मान करती हूं। बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि लेकिन मैं उस फैसले को स्वीकार नहीं करता जो कहता है कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा. अगर जरूरत पड़ी तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत पलटवार करते हुए पूछा ममता जी ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो कहे कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते?

एक नजर 'राजनीतिक मुजरे' पर

अजय बोकिल

इसके पहले कि 'म' से शुरू होने वाला हिंदी का कोई नया शब्द इस चुनाव में राजनीतिक रंगत और मजहबी तल्खी लेकर आए, चुनाव आयोग को धन्यवाद कि वह लोकसभा चुनाव सातवें चरण में ही निपटा रहा है। इन सात चरणों में 'म' के पहाड़े में अंतिम (ऐसा मान लेने में हर्ज नहीं) और छठा शब्द 'मुजरा' रहा। अगर इसे चरणवार देखें तो चुनाव के पहले चरण के पूर्व 'म' से मछली के साथ इसकी शुरुआत हुई। देवी भक्तों के नवरात्रि के उपवास शुरू होने के साथ इंडिया गठबंधन द्वारा 'खाने की आजादी' के संदेश के साथ सनातनियों की भावनाओं पर यह पहली चोट थी, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने साथ में मछली भक्षण के स्वाद का वीडियो वायरल किया।

यह बात अलग है कि साहनी खुद एनडीए में बीजेपी द्वारा उनके बजाए 'बड़ी मछली' को तवज्जो दिए जाने से नाराज होकर राजद गाड़ी में सवार हो गए। उसके बाद 'म' का सफर मंदिर, मस्जिद, मटन और मंगलसूत्र से लेकर मुजरे पर आ टिका। 'म' से शुरू होने वाले हिंदी शब्दों में कितनी राजनीतिक ताकत, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष वार करने की ताकत होती है, यह पूरे देश ने देखा। यानी जो सिलसिला मछली से शुरू हुआ था, फिलहाल उसे मुजरे पर जाकर खत्म समझा जाए। मुजरे का यह समापन किसके हक में होगा, यह तो 4 जून को तय होगा। तब तक दावों की महफिलों में जीत का मुजरा करते रहने का हक हर किसी को है। वैसे 'मुजरा' पसंद करने वाले कई शौकीन इस शौक का दि एंड स्वादिष्ट मछली खाकर भी करते रहे हैं।

बहरहाल बात मुजरे की। यूं तो इस देश में हर चुनाव नेताओं का जनता के आगे वोटों की खातिर 'मुजरा' ही होता है लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उसे मुस्लिम वोटों की खातिर अल्पसंख्यकों के आगे 'मुजरा' करने वाला बताया तो विपक्ष भड़क उठा। विपक्षी नेताओं ने मोदी पर निहायत घटिया भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यह बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री भाषा को लेकर उन पर लगाए गए आरोपों की चिंता करने में वक्त नहीं गंवाते। वो नित नए शब्दों और व्याख्याओं की खोज में रहते हैं, जिनके हर बार नए और सधे हुए राजनीतिक मायने सिद्ध हों। हालांकि विपक्ष चाहता तो इसी 'मुजरे' को यह कहकर उलटा सकता था कि अगर मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए की जाने वाली हर राजनीतिक कोशिश और कॉम्प्रोमाइज 'मुजरा' है तो बहुसंख्यक हिंदू वोट हासिल करने के लिए की जाने वाली सियासी तदबीरें क्या हैं? लेकिन उसने वैसा नहीं किया।

यूं मुजरा अरबी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है, झुककर अभिवादन करना। अलबत्ता अभिवादन की इस कसरती शैली में आदर के साथ साथ लाचारी, चापलूसी और सामंती शैली का महिमामंडन भी शामिल रहा है। जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो मुजरा क्यों करे? वैसे मराठी भाषा में 'मुजरा' एक सम्माननीय और कुलीन शब्द है। लेकिन चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस मुजरे को जिस अर्थ में लिया और पीएम का संकेत भी शायद उसी ओर था, वह था, 'मुजरे' का तवायफों के नृत्य से रिश्ता। तवायफें ये मुजरा अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए करती रही हैं।

यह उनकी आजीविका का साधन है। आज भी कई शहरों में वेश्याओं के इलाके में 'मुजरे' होते हैं। हिंदी फिल्मों में तो 'मुजरे' को बहुत ग्लैमराइज किया गया है। मुगलकाल में मुजरे का अर्थ बादशाहों, राजाओं के आगे अदब से झुक कर तीन बार सलाम करना ही था, इस संस्कृति को उस जमाने में हर राजा और नवाब ने अपना लिया था, जो अंग्रेजों के आने के बाद ही बंद हुआ। अब लोकतांत्रिक भारत में मुजरे की अलग- अलग परिभाषाएं हैं। मसलन मुसलमानों को आरक्षण के लिए किया जाने वाला मुजरा ' साम्प्रदायिक मुजरा' है तो एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण को कायम रखने के लिए किया जाने वाला मुजरा 'सामाजिक न्याय वाला मुजरा' है।

अपनी सत्ता को बचाने के लिए गया मुजरा देशहित में किया गया मुजरा है तो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े बड़े वादों का मुजरा देशविरोधी मुजरा है। जमीनी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे उठाना 'जमीनी मुजरा' है तो सपनो का रॉकेट आसमान में उड़ाना 'सपनीला मुजरा' है। यूं चुनाव में राजनेता और राजनीतिक दल कोई सा भी मुजरा करें, लेकिन सियासी पार्टियों के कामकाज और नेतृत्व के राग रंग देखें तो लगता है कि असली मुजरा तो वहीं हो रहा है। आज देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो, जिसमें आगे बढ़ने के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को जमे हुए नेताओं के आगे मुजरा न करना न पड़ता हो। फर्क इतना है कि यहां नाम अलग- अलग होते है। कहीं वह हाईकमान है तो कहीं शीर्ष नेतृत्व। कहीं वह कमेटी तो कहीं बोर्ड तो कहीं ब्यूरो।

आज कांग्रेस से लेकर भाजपा तक में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि रहनुमाओं के रहमो-करम के बगैर वहां कोई बंदा एक इंच भी आगे बढ़ा हो। कब क्षत्रप कहे जाने वाले बंदे रहनुमाओं का हुक्का भरने लगे, कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक मुजरे की एक खासियत यह भी है कि यहां बादशाह की मानिंद जो एक बार मसनद पर जम गया, वह किसी के हिलाए नहीं हिलता। तवायफों के यहां मुजरे की महफिल तो रात में शमा बुझने के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन राजनीतिक मुजरे की मशाल कभी बुझती नहीं है।

फकत शकलें बदल जाती हैं। किरदार वही और उसी रौब में रहते हैं। इसी तरह तवायफों के मुजरे में ग्राहक को सबकुछ मानकर उसे खुश करना ही उद्देश्य होता है। लेकिन राजनीतिक मुजरे में कई फैक्टर काम करते हैं। जिसमें आला हुजूर की खुदा की मानिंद तारीफ और हर वक्त और शै में कसीदे काढ़े पाने का हुनर भी शामिल है। राजनीतिक मुजरे के कार्टूनों को हर घड़ी हाईकमान के इकबाल की बुलंदी के रखवाले की भूमिका में जीना पड़ता है। जरा भी चूके तो कुर्सी गई समझो। कभी कांग्रेस में ऐसा ही हुआ करता था आजकल भाजपा में शिद्दत से हो रहा है। इसके बरक्स परिवारवादी पार्टियों का मुजरा थोड़े अलग किस्म का है।

यहां परिवार के लोग ही ग्राहक और तवायफ दोनों भूमिका में एक साथ होते हैं। लिहाजा उनकी राजनीतिक नृत्य शैली में ज्यादा प्रकार नहीं होते। लिहाजा यहां रेवड़ी भी अंधों की तरह बंटती है। इनके अलावा एक चौथी नस्ल भी है, जो अपनी जाति या समाज के आधार पर राजनीतिक मुजरों का स्टार्ट अप चलाती है। यानी कि एक मुजरे में तबला बजाने वाला कब दूसरी पार्टी की महफिल में हारमोनियम बजाने लगे, कह नहीं सकते। वैसे भी मुजरे की महफिल साज बजाने वाले साजिंदों की अपनी अलग सियासत होती है। कभी वो ग्राहक का दामन थाम लेते है तो भी तवायफ के आंचल से किस्मत बांध लेते हैं। राजनीतिक शब्दावली में इन सियासी साजिंदों को छोटे और सौदेबाज दल कहा जाता है। ये कब किसके आगे घूंघट उठा दें और कब गिरा दें, कहा नहीं जा सकता।

एक और फर्क भी है। तवायफों के मुजरे को तथाकथित संभ्रांत लोग भले घटिया माने, लेकिन तहजीब और शालीनता का पर्दा वहां अब भी कायम रहता है। शायद इसीलिए गुजरे जमाने में अमीर और रसूख वाले लोग अपनी औलादों को तहजीब और नफासत सीखने के लिए तवायफों के पास भेजा करते थे। लेकिन लगता है कि आजकल के राजनीतिक मुजरों में ये एलिमेंट पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। कोठेवालियों के भी अपने कुछ उसूल और मर्यादाएं थीं, राजनेता इस मामले में तवायफों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। यहां हर नाच सत्ता की ताल पर होता है। ऐसे में राजनीति को मुजरा कहा जाए तो वह इल्जाम कम आत्म स्वीकृति ज्यादा है। मिर्जा गालिब बहुत पहले कह गए थे- ये बंद कराने आये थे तवायफों के कोठे मगर सिक्के की खनक सुनकर खुद मुजरा कर बैठे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगराजोपनिषद्

यह योगपरक उपनिषद् है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह योगपरक उपनिषदों में श्रेष्ठ है, तभी इसे योगराज संज्ञा प्रदान की गई है। इसमें कुल 21 मन्त्र हैं, जिसमें योग विषयक सिद्धान्तों को बड़े सरल शब्दों में व्याख्यायित किया गया है। सर्वप्रथम चार योगों-मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग का उल्लेख है। इसके बाद योग के प्रमुख चार अंगों आसन, प्राणसंरोध (प्राणायाम), ध्यान तथा समाधि का विवेचन है। पुनः 9 चक्रों (ब्रह्मचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र, हृदयचक्र, कण्ठचक्र, तालुकाचक्र, भ्रूचक्र, ब्रह्मरन्ध्रचक्र, व्योमचक्र) का वर्णन तथा उनमें ध्यान करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अन्त में चक्रों के ध्यान की फलश्रुति बताते हुए उपनिषद् को पूर्णता प्रदान की गई है।

अब योगियों के योग-सिद्धि के लिए मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग इन चार प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद् का वर्णन करते हैं। योग के तत्त्वदर्शियों ने योग को आसन, प्राणसंरोध, ध्यान तथा समाधिरूप चार प्रकार का कहा है।

ये चारों सर्वयोग-सम्मत कहे गये हैं। मन्त्रयोग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि हैं एवं लययोग को व्यासादि ने सिद्ध किया। नौ प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तीन बार आवृत्त (घिरा हुआ) भग (त्रिकोण) की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्मचक्र कहा गया है।

अपान के स्थान में कामरूपी मूलकन्द स्थित है, उसको ही अग्नि कुण्ड एवं तत्त्व कुण्डलिनी कहा है। उस ज्योतिस्वरूप जीवरूपिणी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है। प्रवालाङ्कुर (रक्त वर्ण के अंकुर) के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिङ्ग स्थित है।

क्रमशः ...

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

अवधेश पैन्यूली

दुनिया भर में हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे या एंटी-टोबैको डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू विरोधी दिवस कहते हैं। हर कोई जानता है कि तंबाकू खाना उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसके सेवन से कभी परहेज नहीं करते। इसलिए, तंबाकू विरोधी दिवस पर लोगों को जागरूक करने, तंबाकू को छोड़ने और कभी हाथ नहीं लगाने के लिए जागरूक किया जाता है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय या उसकी थीम यानी तंबाकू उद्योग की दखल से बच्चों की रक्षा करना है ताकि भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंबाकू के इस्तेमाल में गिरावट जारी रहे। इस साल, तंबाकू उद्योग के युवाओं को टारगेट कर बनाए गए मार्केटिंग के तरीकों की चिंता बढ़ाने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया गया है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह के जरिए दुनिया भर में युवा तेजी से तंबाकू प्रोडक्ट्स के आकर्षण और संपर्क में आ रहे हैं। यह उनके स्वास्थ्य और समाज के कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर के सर्वेक्षण लगातार दिखा रहे हैं कि ज्यादातर देशों में 13-15 वर्ष की आयु के बच्चे तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं में धूम्रपान का प्रचलन बना हुआ है और कई देशों में यह बढ़ रहा है।

13 से 15 वर्ष की आयु के 38 मिलियन से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2022 में, 15 से 24 साल के बच्चों के बीच पॉपुलर टीवी और वेब शो में तंबाकू वाले विजुअल्स में 110 फीसदी की वृद्धि हुई, जो अक्सर धूम्रपान को ग्लैमरस और कूल के रूप में दिखाते हैं। ट्रूथ इनिशिएटिव के अनुसार, स्क्रीन पर धूम्रपान की तस्वीरें देखने पर युवाओं में स्मोकिंग शुरू करने की संभावना तीन गुना तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने साल 1987 में संकल्प WHA40.38 पारित कर 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की अपील की। इस दिन का मकसद दुनिया भर में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को 24 घंटे के लिए तंबाकू उत्पादों छोड़ने के लिए राजी करना था।

अगले साल 1988 में संकल्प WHA42.19 पास कर हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाना तय किया गया था। पहले साल यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1988 की थीम थी तम्बाकू या स्वास्थ्य : स्वास्थ्य चुनें। इसके दस साल बाद 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू मुक्त पहल की स्थापना की, जो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों और स्वास्थ्य से जुड़े तंबाकू के मुद्दे पर ध्यान देने की पहल है।

नवाज ने की गलती कबूल, शहबाज सुधारेंगे भूल!

अभिनय आकाश

उठो कबड्डी- कबड्डी खेलेंगे सरहदों पर,
जो आये अब के तो लौटकर फिर ना जाये कोई

वैसे तो भारत-पाकिस्तान की सरहद पर जंग होती है कोई खेल नहीं, लेकिन कहा जाता है कि शायरों की रूह रूहानी होती है और गुलजार ने ये लाइनें लिखी है।

साल 1999 में फरवरी का महीना था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदा-ए-सरहद की शुरुआत करने लाहौर पहुंचते हैं। सदा-ए- सरहद बस सेवा को नाम दिया गया था जो दिल्ली और लाहौर के बीच शुरू होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अमृतसर से बस को हरी झंडी दिखाने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि साहब हमारे दर तक आए और बिना मिले लौट जाए ऐसा हो नहीं सकता। यात्रा का आगाज मेहमानवाजी से शुरू हुआ। जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बातों से वो समां बांधा कि नवाज शरीफ ने उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का न्यौता तक दे डाला। ये सब सुनकर लगता है कि क्या शानदार लम्हा रहा होगा और दोनों देशों के बीच के रिश्ते कितने अच्छे रहे होंगे। लेकिन ये गर्मजोशी चंद महीनों के बीच पाक सेना के जवान कारगिल में कब्जा करके बैठ गए थे। इस घटना को ढाई दशक गुजर गए हैं और आप कह रहे होंगे की आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजेपयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया। नवाज ने संकेत भी दिए हैं कि भारत की नई सरकार के साथ पाकिस्तान दोस्ती की कोशिश करने वाला है।

भारत के तेवर तो इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ काफी तीखे हैं। वहीं पाकिस्तान के तमाम नेता भारत के सामने हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं।

शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ताजपोशी एक बार फिर से मुस्लीम लीग नवाज के अध्यक्ष के तौर पर हुई। नवाज शरीफ को पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने सबसे बड़े दिन पर अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल कर ली है। नवाज शरीफ ने कबूल किया कि 1999 में इस्लामाबाद ने समझौते का उल्लंघन हुआ। नवाज शरीफ ने ये भी माना कि पाकिस्तान की ये गलती थी। ये समझौता नवाज शरीफ और अटल बिहारी वायपेयी के कार्यकाल के दौरान लाहौर में हुआ था। आम परिषद को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने ये बात कही। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कारगिल में किए गए हमले के संदर्भ में ये बात कही। साल 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ 22 लोग एक बस में वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंचे थे। इन 22 लोगों में वाजपेयी का मंत्रिमंडल, कुछ फॉरेन मिनिस्टर और दिग्गज कलाकार शामिल थे। लाहौर पहुंचते ही अटल बिहारी वाजपेयी का जबरदस्त स्वागत हुआ। वाजपेयी ने कहा कि मैं अपने साथी भारतीयों की सदभावना और आशा लेकर आया हूं, जो पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और सौहार्द चाहते हैं। मुझे पता है कि ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है और मुझे उम्मीद है कि हम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। 21 फरवरी 1999 को पाकिस्तान और भारत के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसे लाहौर समझौता कहा गया।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का एक निर्णायक लम्हा था फरवरी 1999 में उनकी लाहौर बस यात्रा। यह ऐसा फैसला था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आमूलचूल बदलाव लाने की संभावना से वाबस्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बस से लाहौर गये थे और अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाकर अपनी प्रिय छवि की छाप छोड़ी। लाहौर समझौता ज्ञापन स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान परीक्षणों के बारे में एक दूसरे को सूचित करने का संयुक्त उपक्रम है। घोषणापत्र के मुताबिक दोनों देश इस बात पर राजी थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का विकास और मैत्रीपूर्ण सहयोग, दोनों ही देशों के लोगों के हित में सहायक सिद्ध होंगे। जिससे वे अपनी ऊर्जा को बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर सकेंगे। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे समेत सभी मुद्दों को हल करने के अपने प्रयासों को तेजी लाने की बात इसमें कही गई थी।

दोनों देश जम्मू-कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और इस खतरे से निपटने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियारों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घोषणा में सुरक्षा माहौल में सुधार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत विश्वास-निर्माण उपायों के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। सहमत द्विपक्षीय एजेंडे के शीघ्र और सकारात्मक परिणाम के लिए बातचीत प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति हुई। सार्क लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता- घोषणा ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और त्वरित आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। घोषणा में दोनों देशों को सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया।

शांति और सद्भाव के इस समझौते को अभी दो महीने ही नहीं हुए थे कि मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में जंग छेड़ दी। 3 मई 1999 की वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद 18 हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। नवाज को ये भी लगता है कि भारत से संबंध सुधारकर ही पाकिस्तान के अच्छे दिन आ पाएंगे। नवाज शरीफ ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार भारत में नई सरकार के गठन के बाद फिर से संबंध सुधारने की तैयारी कर रही है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो काम 1998 में वो नहीं कर पाए उसे शहबाज शरीफ 2024 में करके दिखाएंगे। यानी भारत से संबंधों को सुधारेंगे। शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने भी भारत के साथ व्यापार शुरू करने के संकेत दिए थे। लेकिन जिस शख्स के पास इस सरकार का रिमोट कंट्रोल है। उसके बयान के बाद साफ है कि सुलह की कोशिशें शुरू कर दी गई है। अब भारत में नई सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान की पेशकश पर फैसला हो सकता है।

आज का इतिहास

1935 ब्रिटिश राज के बलूचिस्तान में 7.7 मेगावॉट के भूकंप ने पाकिस्तान के 30,000 से 60,000 लोगों को कहीं भी मार डाला।

1935 पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भीषण भूकंप से 50 हजार से अधिक लोगों की मौत।

1941 यूनाइटेड किंगडम ने इराक के अपने कब्जे को पूरा कर लिया, अब्द अल-इलाह को फैसल II के लिए रीजेंट के रूप में सत्ता में वापस कर दिया।

1961 दक्षिण अफ्रीका संघ दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन गया। यह चार अलग ब्रिटिश उपनिवेशों के एकीकरण के साथ अस्तित्व में आया : केप कॉलोनी, नेटाल कॉलोनी, ट्रांसवाल कॉलोनी और ऑरेंज रिवर कॉलोनी।

1981 पुलिस और सरकार द्वारा प्रायोजित भीड़-भाड़ वाली एक संगठित भीड़ ने श्रीलंका के जाफना में सार्वजनिक पुस्तकालय को जलाना शुरू कर दिया, जो 20 वीं शताब्दी के बेथलॉनिकलस्म के सबसे हिंसक उदाहरणों में से 97,000 से अधिक वस्तुओं को नष्ट कर दिया।

1986 1986 फीफा विश्व कप मेक्सिको में शुरू हुआ

1994 दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आन्दोलन का 109वाँ सदस्य राष्ट्र बना।

1999 कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये नेपाल के पहले संसद के पहले सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना के बाद नेपाल के पहले प्रधानमन्त्री थे।

2005 मैगज़ीन वैनिटी फेयर के एक लेख में पता चला है कि गुप्तचर जिसे डीप थ्रोट के नाम से जाना जाता है, जिसने वाटरगेट कांड के बारे में जानकारी दी थी, वह एफबीआई के पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर मार्क फेल्ट थे।

2009 अमेरिकी चिकित्सक जॉर्ज टिलर, जो राष्ट्रीय स्तर पर देर से गर्भपात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ डॉक्टरों में से एक होने के लिए जाने जाते थे, को स्कॉट रोजरर द्वारा गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

2010 गाजास्ट्रिप की चल रही नाकेबंदी को तोड़ने के प्रयास के दौरान, इजरायली नेवी, एमवी मावी मम्मारा के चालक दल के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगे, जिसके परिणामस्वरूप नौ नागरिक मौतें हुईं।

मुसलमानों के लिए अमेरिकी चिंता की खतरनाक वास्तविकता

मनोज ज्वाला

खबर है कि रिलीजियस मजहबी स्वतंत्रता की स्वयंभूव ठेकेदार बनी अमेरिकी सरकार भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बडी चिन्तित है। वह चिन्तित इसलिए नहीं है कि भारत में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक 43 प्रतिशत की दर से बढ चुकी है और भारतीय मुसलमानों की विभिन्न जिहादी गतिविधियों से यहां के अनेक राज्यों में बहुसंख्यक हिन्दू समाज त्राहि-त्राहि कर रहा है; अपितु वह 'न्यूयॉर्क टाइम्स' नामक एक अमेरिकी अखबार की उस रिपोर्ट को ले कर चिन्तित है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में 'धर्मनिरपेक्ष ढांचा और मजबूत लोकतंत्र कमजोर' हुआ है।

मालूम हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ही देश में अजनबीः मोदी के भारत में मुसलमान होना शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में मुस्लिम समाज पीड़ा और अलगाव से जूझ रहा है। वे अपने बच्चों को ऐसे देश में पालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनकी पहचान पर सवाल उठा रहा है। इस अखबारी समाचार बनाम दुष्प्रचार पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा है कि वह इस मामले पर भारत सहित दुनिया भर के देशों के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि वह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम दुनिया भर में सभी के धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। मिलर ने आगे यह भी कहा है कि हमने भारत समेत कई देशों के साथ धार्मिक समुदायों के लिए समान रिलीजियस व्यवहार के महत्व पर चर्चा की है।

यहां यह गौरतलब है कि 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट और उस पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है, जब भारतीय मुसलमानों की आबादी में सर्वाधि 43त्न की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है और सारा मुस्लिम समाज एकजुट हो कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध संसदीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए 'वोटिंग जिहाद' का संगठित अभियान चला रहा है। इससे पहले यह मजहबी समाज देश के कई राज्यों में अपनी संगठित शक्ति के बुते शासन-प्रशासन पर काबिज हो कर वहां से धार्मिक समाज के लोगों (हिन्दुओं) को विस्थापित होने को बाध्य कर चुका है और फिलवक्त अनेक राज्यों की सियासत को अपने हिसाब से संचालित करने की हैसियत प्रदर्शित कर रहा है। इतना ही नहीं, वह भारतीय संविधान से इत्तर 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के सहारे विशेषाधिकारों की मलाई चाभ रहा है और 'मुस्लिम वक्फ बोर्ड' की लाठी से सरकारी-गैरसरकारी भू-खण्डों पर कब्जा करते हुए लाखों हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व हासिल कर सेना व रेलवे के बाद सबसे बडा भू-स्वामी बना हुआ है। जगजाहिर है कि भारत में मुसलमानों की हालत व हैसियत जितनी अच्छी है, उतनी मुस्लिम देशों में भी नहीं है। जबकि पडोसी पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 90त्न से भी ज्यादा घट गई है और वहां वे इस्लामिक स्टेट-संरक्षित उत्पीडन का इस कदर शिकार होते रहे हैं कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार को उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का कानून बनाना पडा है।

बावजूद इसके, अमेरिकी मीडिया इण्डस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री को भारत में ही मुसलमान आपदग्रस्त

दीख रहे हैं, तो यह उनका दृष्टि-दोष नहीं है, अपितु एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी प्रपंच है, जिसके सूत्र-समीकरण उस अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के हाथों में हैं, जिसने अभी हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर भारत को 'धार्मिक स्वतंत्रता का हननकर्ता' बताते हुए विशेष चिन्ता वाले देशों की सूची में शामिल कर रखा है। यूएससीआईआरएफ के लगभग सभी सदस्य रिलीजियस विस्तारवादी चर्च मिशनरियों से सम्बद्ध है, जबकि इस आयोग का गठन ही अमेरिका ने वेटीकन-पोप के दबाव में 'इण्टरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट' नामक कानून बना कर उसी के तहत कायम किया हुआ है । देखने-सुनने में तो यह अधिनियम दुनिया के सभी राष्ट्रों के भीतर वहां के नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी रिलीजन-मजहब अथवा धर्म को अपनाने-मानने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के बावत इसकी वकालत करता है; किन्तु वास्तविक व्यवहार में यह 'धर्म (सनातन) त्यागने व रिलीजन-मजहब अपनाने' का मार्ग प्रशस्त करता है और इस हेतु चर्च-मिशनरी-संस्थाओं (एनजीओ) को सरंक्षित करता है। यही कारण है कि इस अमेरिकी अधिनियम के वैश्विक क्रियान्वयन की निगरानी करने वाला वह आयोग (यूएससीआईआरएफ) भारत में कायम धर्मान्तरण-रोधी कानूनों और विदेशी धन से संपोषित मिशनरी संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भारतीय कानूनों पर आपत्ति जताते रहता है, जैसा कि उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि- बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया, घृणास्पद बयानबाजी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही, जिससे मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी असमान रूप से प्रभावित हुए। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एवं धर्मांतरण व गोहत्या विरोधी कानूनों के लगातार लागू होते रहने के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, निगरानी की गई और निशाना बनाया गया।

मेरी एक पुस्तक- 'भारत के विरुद्ध पश्चिम के बौद्धिक षड्यंत्र' में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, अर्थात बे-रोक-टोक धर्मोन्मूलन व ईसाईकरण शीर्षक से एक अध्याय संकलित है, जिसमें अनेक प्रामाणिक तथ्यों से मैंने यह सिद्ध किया हुआ है कि यह अधिनियम वस्तुतः भारत राष्ट्र के विघटन व सनातन धर्म के उन्मूलन एवं हिन्दू-समाज के ईसाइकरण-इस्लामीकरण का मिशनरी हथकण्डा और लक्षित देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का अमेरिकी फण्डा मात्र है। यह आयोग इस्लामी जेहाद का भी मौन समर्थन करता है, क्योंकि ईसाइयत और इस्लाम दोनों ही धर्म-विरोधी एवं पैगम्बरवादी होने के कारण परस्पर सहयोगी हैं और इन दोनों का विरोध केवल व केवल धर्म (सनातन) से, अर्थात धर्मधारी भारत राष्ट्र व हिन्दू समाज से है। इस अमेरिकी आयोग ने हिंदुओं के बलात यीसाइकरण व इस्लामीकरण पर कभी सवाल नहीं उठाया है; बल्कि धर्मोन्मूलन (धर्मान्तरण) विरोधी भारतीय कानूनों पर ही सदैव आपत्ति जताते रहा है, क्योंकि इन कानूनों से चर्च-मिशनरियों के विस्तारवादी अभियान में बाधायें उत्पन्न होती हैं।

मालूम हो कि अमेरिका ईसाइयों की सर्वोच्च नीति-नियामक सत्ता- वेटिकन सिटी से संचालित समस्त मिशनरी संस्थाओं का संरक्षक बना हुआ है। और इन संस्थाओं के प्रतिनिधि अमेरिकी सरकार की वैदेशिक नीति विषयक मार्गदर्शक हुआ करते हैं। इसी दुरभिसंधि के तहत अमेरिका पूरी दुनिया भर में स्वतंत्रता-समानता-लोकतंत्र व मानवाधिकार की निगरानी-पहरेदारी करने वाला चौधरी बना हुआ है इस चौधराहट की आड में वेटिकन चर्च का एजेण्डा क्रियान्वित करते रहता है। 'टाईम' और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' जैसे मीडिया संस्थान भी इस दुरभिसंधि के साझेदार हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार से यूएससीआईआरएफ को यह तथ्य व सत्य नहीं सूझता, उसी प्रकार से 'न्यूयॉर्क टाइम्स' को भी यह नहीं दिखता कि भारत-विभाजन के वक्त पाकिस्तान में तकरीबन ढाई करोड हिन्दू रह गए थे और लगभग उतने ही मुसलमान भारत में रह गये थे, किन्तु आज पाकिस्तान में शासन-संरक्षित मुस्लिम आतंक से पीडित-प्रताडित-धर्मांतरित-विस्थापित होते रहने के कारण हिन्दूओं की आबादी घट कर बीस लाख (दस प्रतिशत) से भी कम हो गई है, जबकि भारत में शासन से तुष्टिकृत-उपकृत होते रहने के कारण मुसलमानों की आबादी बढ कर पैंतीस करोड से भी ज्यादा हो गई है।

पीओके में बढ़ता जा रहा है जनता का गुस्सा

विवेक शुक्ला

जब हमारी कश्मीर घाटी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के बहुत बड़े हिस्से में अवाम सड़कों पर है। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से मात्र 130 किलोमीटर दूर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे प्रमुख शहर में जनता सरकार से दो-दो हाथ करना चाहती है। जनता पीओके सरकार और देश की संघीय सरकारों से अपना हक मांग रही है। पीओके में जब आंदोलन चल रहा है, तब भारत के लोकसभा चुनाव की कैंपेन में पीओके का जिक्र हो रहा है। भाजपा नेता एवं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे। पीओके को भारत में मिलाने को लेकर भारतीय संसद का एक अहम प्रस्ताव भी है। पीओके की बिगड़ती स्थिति के कारण पाकिस्तान के रहनुमाओं की रातों की नींद उड़ गयी है। पाकिस्तान तो भारत के जम्मू-कश्मीर पर बार-बार अपना दावा करता है, पर दुनिया देख रही है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है। पीओके का अवाम बिजली की भारी-भरकम बिलों और आटे के आसमान छूते दामों के कारण नाराज है। सोशल मीडिया के दौर में पीओके की जनता देख रही है कि भारत के कश्मीर के लोग कम से कम बिजली के बिलों या आटे की आसमान छूती कीमतों के कारण तो नाराज नहीं है। वहां अन्य मसले हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर जीवन सुकून भरा है। पीओके में ताजा हिंसक आंदोलन का तात्कालिक कारण है कि पाकिस्तान सरकार ने आटे की कीमतों को कम करने की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। बिजली के बिल कम करने पर तो सरकार आंदोलनकारियों से बात करने को वैसे भी तैयार नहीं है। दरअसल, पीओके में बवाल तब शुरू हुआ जब अवामी एक्शन कमेटी ने आठ मई, 2023 को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किये थे। इससे पहले, बीते वर्ष अगस्त में बिजली बिल पर नये कर लगाने से स्थिति बिगड़ने लगी थी। करों के विरोध में मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया जिन्हें स्थानीय व्यापारियों का समर्थन मिला। प्रदर्शन जल्दी ही रावलकोट और मीरपुर जिलों तक फैल गया। बीते वर्ष 17 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बैठक के बाद आवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन को राज्यव्यापी करने का निर्णय लिया। इसके बाद पीओके में बिजली बिल जलाये जाने लगे। इससे नाराज सरकार ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, पर जनता के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार को 10 सूत्रीय मांगों की सूची सौंपी गयी। जिसमें आटे पर सब्सिडी और बिजली बिलों में कमी की मांगें शामिल थीं। पर सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इससे नाराज आवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद स्थित पीओके विधानसभा तक मार्च करने का आह्वान किया। नौ मई को डोडियाल में एक डिप्टी कमिश्नर पर उस समय हमला हुआ जब उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश दिये। दस मई को पीओके के प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने निकले, जिससे गंभीर झड़पें हुईं। एक आला पुलिस अफसर की मौत हो गयी। इसके बाद से ही पीओके के मुख्यमंत्री अनवर उल हक सरकार को जनता के गुस्से से दो-चार होना पड़ रहा है। फिलहाल लगता तो यही है कि आवामी एक्शन कमेटी का अपनी मांगों के समर्थन में चल रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती। हां, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच रावलकोट में बातचीत फिर से शुरू जरूर हो गयी है। परंतु, यह देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान सरकार, जो पीओके सरकार के साथ खड़ी है, प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार करेगी?

बांग्लादेश को तोड़कर नया ईसाई देश बनाएगा अमेरिका ?

अभिनय आकाश

अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा अमेरिका अब छोटे देशों पर अपनी बादशाहत मनवाकर दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा कराएगा? अमेरिका के मित्र राष्ट्र और दुश्मन तो मान नहीं रहे। भारत पर भी इसने अपने ट्रैप को फेंका था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। ऐसे में बाइडेन की मुसीबतें बढ़ी है। लेकिन अमेरिका की उम्मीदें ऐसे देश पर आकर टिकी है जो भारत का पड़ोसी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने बयान से देश-दुनिया को चौंका दिया। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने जब कहा कि अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सैन्य अड्डे के लिए बेचैन अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार से नया देश बनाने की साजिश रच रहा है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पार्टी मीटिंग में कहा कि एक गोरा आदमी हमसे चाहता है कि हम उन्हें एक बेस बनाने दें। इतना ही नहीं धर्म के आधार पर एक नया देश बनाए। शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एक ईसाई बहुल मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसे बनाने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सा भारत का भी शामिल करके इसे बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ईस्ट तिमोर का मॉडल कॉपी किया जाएगा। बांग्लादेश की पीएम का कहना है कि अमेरिका कुकी चिन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर कुछ ऐस प्लानिंग कर रहा है।

18 वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था और 1975 तक उसके नियंत्रण में रहा। जब पुर्तगाली वापस चले गए , तो इंडोनेशिया के सैनिकों ने आक्रमण कर पूर्वी तिमोर को उसके 27 वें प्रांत के रूप में अपने में मिला लिया। स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और खूनी संघर्ष चला, जिसके दौरान कम से कम 1,00,000 लोग मारे गए। 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरवासियों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया,

लेकिन इससे हिंसा और भी बढ़ गई, जब तक कि शांति सेना को प्रवेश की अनुमति नहीं दे दी गई। देश को 2002 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी ।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ ऐसे ही ग्रुप हैं, जिनके अपने हित हैं। जिसे चीन व अन्य देशों की तरफ से हवा दी जाती रहती है। लेकिन ये फैली हुई आग अब बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है। बांग्लादेश में मुस्लिम अधिक संख्या में है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बहुत से राज्यों की डेमोग्राफी काफी भिन्न है। मिजोरम में ईसाई समुदाय ज्यादा संख्या में है। मणिपुर में 40 प्रतिशत ईसाई हैं। कुकी जनजाति ईसाई बहुल है। चिन से भी ईसाई जनजाति माइग्रेट होकर वहां गई है। मिजोरम से असम कनेक्ट है। यही से उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का रोल शुरू हो जाता है। उल्फा से एक अलग देश की मांग उठाने की साजिश है। कुकी नेशनल फ्रंट को अमेरिका बांग्लादेश में एक नया देश बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल, दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के 175 से अधिक बेस बने हुए हैं। यहां अमेरिकी फोर्स मौजूद हैं। दुनियाभर में अमेरिका के दो लाख सैनिक की मौजूदगी है। अमेरिका दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में अपना बेस बनाकर छोड़ देता है। लेकिन म्यामांर, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश हो या भारत अमेरिकी बेस की मौजूदगी नहीं है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील माना जाता है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए ऐसी प्लानंग कर रहा है।

वाशिंगटन की नजर कई वर्षों से बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक छोटे से द्वीप सेंट मार्टिन पर है, जो बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। केवल 3 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह द्वीप कॉकस बाजार-टेकनॉफ प्रायद्वीप से लगभग 9 किमी दक्षिण में स्थित है। बांग्लादेश एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर (रिटायर्ड) सदरुल अहमद खान ने स्पुतनिक इंडिया से कहा, %बांग्लादेश तब तक समर्थन देने के लिए तैयार है, जब तक यह शांति-रक्षा अभियानों, मानवीय सहायता या सैन्य अभ्यास तक सीमित है।% खान ने बताया कि अमेरिका लंबे समय से सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश ऐसी सैन्य महत्वाकांक्षाओं की निंद करता है जो हमारी संप्रभुता को नष्ट कर देगी और दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता को प्रभावित करेगी।

भारत और चीन दोनों न केवल बांग्लादेश के साथ उनके मजबूत आर्थिक संबंधों के कारण, बल्कि क्षेत्र में उनकी व्यापक प्रतिद्वंद्विता के मद्देनजर भी। ढाका दो एशियाई दिग्गजों से साझेदारी की अपेक्षाओं को कैसे प्रबंधित करता है यह महत्वपूर्ण है, और इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जाएगी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत का समर्थन चीन के पाकिस्तान के समर्थन के विपरीत है। इस इतिहास के बावजूद, व्यावहारिकता इन पड़ोसियों के साथ बांग्लादेश के वर्तमान संबंधों को आकार देती है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 15 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। भारत बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पूर्वी बफर के रूप में मान्यता देता है, और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक बंदरगाहों और पावर ग्रिड पहुंच में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। ऐतिहासिक संबंध और भौगोलिक निकटता एक सहजीवी व्यापार संबंध को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, चीन के साथ बांग्लादेश का दोतरफा व्यापार 2022 में 25 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

ऋषि सुनक का जोखिम भरा आखिरी दांव

शिवकांत

ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अमेरिकी स्वाधीनता दिवस चार जुलाई के दिन आम चुनाव कराने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। चुनाव में संभावित हार से भयभीत उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसद सकते में हैं और नाराज हैं। लंबे अरसे से चुनाव की मांग कर रही विपक्षी लेबर पार्टी को भी हैरानी हुई है।

इसका मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पार्टी लोकमत सर्वेक्षणों में विपक्ष के नेता किएर स्टॉमर और उनकी लेबर पार्टी से 20-22 अंक पीछे चल रहे हैं। लोकप्रियता में इतना पीछे रहते हुए किसी प्रधानमंत्री ने समय से पहले चुनाव कराने का जोखिम नहीं उठाया है। उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि वे 25 अक्तूबर को अपने कार्यकाल के दो साल पूरे करने के बाद क्रिसमस से पहले चुनाव करायेंगे। वर्तमान संसद का कार्यकाल 17 दिसंबर को पूरा होने वाला था, जिसके बाद 25 दिनों के भीतर चुनाव कराये जा सकते थे। इससे उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों को सकारात्मक प्रभाव दिखाने के लिए छह महीने का समय और मिल सकता था। इसलिए अधिकतर लोग पहले चुनाव कराने के प्रधानमंत्री सुनक के फैसले को उनके आखिरी दांव के रूप में देख रहे हैं। उन्नीस माह के कार्यकाल में उनका कोई दांव नहीं लग पाया।

महंगाई दर नीचे आने के बावजूद चीजों के दाम 2021 की तुलना में करीब 20 प्रतिशत ऊपर हैं, इसलिए लोगों को आर्थिक तंगी से राहत महसूस नहीं हो रही है। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद महंगाई में उतनी गिरावट नहीं आयी है कि जिससे आश्वस्त होकर बैंक अपनी ब्याज दरें घटाना शुरू करें। ऊर्जा संकट कम तो हुआ है, पर यूक्रेन और गाजा के युद्धों की वजह से उसके लौटने का खतरा बना हुआ है। कोविड महामारी पर हुए खर्च से बिगड़े बजट को काबू में लाने के लिए सार्वजनिक खर्चों में की जा रही कटौती से स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, समाज कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे लोग नाराज हैं। नौकाओं से ब्रिटिश चैनल पार कर अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों की संख्या गर्मियों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप्रवासन में आया गिरावट का रुझान बदल सकता है। विपक्ष इसे

चुनावी मुद्दा बना सकता था। वैसे भी प्रधानमंत्री सुनक के लिए लेबर पार्टी से कहीं बड़ा सिरदर्द उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी का ही वह दक्षिणपंथी खेमा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन का समर्थक था। उनके नेता चुने जाने के दिन से ही किसी न किसी बहाने से उनके खिलाफ पार्टी में बगावत भड़काने की कोशिशें चलती रही हैं। इसी महीने के आरंभ में हुए निकाय और महापौर चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से इनमें और तेजी आ रही थी।

लगता है इन सारी संभावनाओं को देखकर और तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार और पार्टी की तथा अपनी लोकप्रियता में कोई सुधार न होता देखकर ही प्रधानमंत्री ने जुआ खेला है। इस महीने की रिपोर्टों के मुताबिक महंगाई दर घटकर 2।3 प्रतिशत हो गयी है और अर्थव्यवस्था की गति भी अपेक्षा से अधिक है। बेरोजगारी रिकॉर्ड न्यून स्तर पर है और आप्रवासियों की संख्या में भी पिछले साले की तुलना में दस प्रतिशत की कमी आयी है। उन्हें लगता है कि यही वह घड़ी है, जिसमें वे हारती बाजी को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो यह ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर साबित होगा, जो सर्वेक्षणों पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। प्रधानमंत्री सुनक की चुनावी घोषणा के भाषण से लगता है कि वे मुख्यतया दो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं- अर्थव्यवस्था को कोविड, ऊर्जा संकट और लिज ट्रस सरकार की 'कर्ज लेकर खर्च करो' की नीति से पैदा हुए महंगाई के संकट से निकाल कर विकास की पटरी पर लाने का उनका रिकॉर्ड तथा अवैध शरणार्थियों की बाढ़ रोकने के लिए उन्हें रुआंडा भेजने की योजना। उनका दावा है कि विपक्ष के पास समाधान की कोई ठोस नीति नहीं है। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी लेबर पार्टी नेता किएर स्टॉमर का कहना है कि ब्रिटेन के सारे संकटों के लिए कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल का कुशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। अर्थव्यवस्था को ब्रेक्जिट से तबाह करने और पांच साल में चार प्रधानमंत्री बदलने वाली पार्टी को बदले बिना न अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है और न स्थिर सरकार मिल सकती है। लगता है लेबर पार्टी बदलाव और स्थिरता के नारे पर ही चुनाव लड़ेगी।

वामपंथी रुझान के कारण लेबर पार्टी की छवि सरकारी विभागों में फिजूलखर्ची करने और उसके लिए पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की रही है। इसलिए लेबर नेता स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रक्षा और बुनियादी सुविधाओं के संकट की बातें तो करेंगे, लेकिन सुधार के लिए खर्च करने के वादों से बचते नजर आयेंगे। यहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वोट बटोरने के लिए मनचाहे लोकलुभावन वादे नहीं कर सकते। वादे करने से पहले उन्हें पूरा करने में लगने वाला पैसा कहां से आयेगा, इसका हिसाब देना पड़ता है। इसलिए यहां वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कोई पार्टी टैक्स बढ़ाकर खर्च करने की नहीं, कटौती और किफायत से बचा कर खर्च करने की बात करती है।

लेबर नेता स्टॉमर को यह भरोसा दिलाना होगा कि अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी सरकार पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पार्टी की उम्मीद का एक आधार लेबर पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ उसके मुस्लिम और वामपंथी समर्थकों में फैला रोष भी हो सकता है, जो इस्राइल द्वारा गाजा विनाश को लेकर लेबर पार्टी के रवैये से नाराज हैं। ब्रिटेन में लगभग 41 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो आबादी का लगभग 6।3 प्रतिशत हिस्सा हैं। संसद की कुल 650 सीटों में से 80 से अधिक सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हो सकता है। इनमें बहुत सी सीटें लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफर्ड, ब्लैकपूल, मैनचेस्टर और ग्लासगो जैसे शहरों में हैं। परंतु लेबर पार्टी का नाराज मुस्लिम और वामपंथी वोट कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लिबरल पार्टी या निर्दलीयों को मिलने की संभावना अधिक है। लेबर पार्टी में इस समय रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम सांसद हैं। मोदी सरकार विरोधी और खालिस्तान समर्थक तत्वों का भी खासा प्रभाव है। इसलिए यदि लेबर सरकार बनती है, जिसकी संभावना प्रबल दिख रही है, तो भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है।

ईरान के लिए क्या है सबसे बड़ा सवाल

अमिताभ सिंह

ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पिछले दिनों हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई अकाल मौत ने ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं। यह घटना इस्राइल-हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। ध्यान रहे, इस संघर्ष में 35,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। खास बात यह कि ईरान इस संघर्ष का एक पक्ष है। यह इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने प्रॉक्सी के जरिए इस्राइली राज्य के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल है और इसे 'प्रतिरोध की धुरी' बताता है। वैसे, शुरुआती जांच के मुताबिक, यह मौत एक दुर्घटना थी। इसके पीछे किसी तरह की अंतरराष्ट्रीय या घरेलू साजिश की संभावना को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इब्राहिम रईसी की इस अचानक और दुखद मृत्यु का पहला प्रभाव ईरानी राजनीति पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, यह है कि रईसी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ईरान के लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इब्राहिम रईसी एक कट्टर धार्मिक प्रचारक थे, जिन्हें अयातुल्लाह अली खामेनेई की अगुआई वाली ईरान की सर्वोच्च परिषद के सदस्यों का वरदहस्त हासिल था। 1980 के दशक में केवल 25 वर्ष की उम्र में वह ईरान के स्टेट प्रॉसीक्यूटर बन गए थे। उन्हें ईरान में इस्लामी शासन की मजबूत नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इस क्रम में वह इस्लामी गणराज्य का विरोध करने वाले बहुत से लोगों की फांसी के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इस्लामी गणराज्य ईरान में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए, उन्हें अक्सर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। बहरहाल, रईसी की मौत किसी भी तरह से ईरानी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगी, इसके कोई आसार नहीं दिखते। हालांकि ईरान में नियमित शासन संचालन में उनकी अहम भूमिका रहती थी और वह कट्टरपंथियों की पसंद माने जाते थे। उनके नेतृत्व में, ईरान ने इस्राइल पर हमला करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और चीन, भारत और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ दोस्ती की। हालांकि उन्होंने या धार्मिक नेतृत्व ने इस्राइल या अमेरिका के साथ सीधे टकराव मोल नहीं लिया, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराने में पीछे नहीं रहे। रईसी की विदेश नीति की प्राथमिकताएं कई लिहाज से सराहनीय मानी जाती हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन किया। उसे ड्रोन की सप्लाई की। रूस भी चीन को पीछे छोड़ते हुए ईरान में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में भी वह उतने ही कामयाब रहे। वह 20 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले ईरानी राष्ट्रपति बने और अरबों डॉलर के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2023 में चीन को ईरान का तेल निर्यात 50% बढ़ गया। उन्होंने 2023 में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सदस्यता दिलाई और 2024 में भारत के आमंत्रण पर वृहद-ब्रिक्स के सदस्य बने। उनके शासन के दौरान ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होना भी एक बड़ी घटना रही। यही नहीं अमेरिका, इस्राइल और अन्य शक्तियों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की योजना जारी रखी। यह त्रासदी ऐसे समय हुई है, जब इस्राइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। अमेरिका और इस्राइल मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए ईरान को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर दबाव में लाने का प्रयास करेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से विवाद का विषय रहा है। इसी के चलते पश्चिम और व्यापक विश्व के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो पाए। अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो संभव है कि ईरान, चीन और रूस के ज्यादा करीब चला जाए। ऐसा हुआ तो क्षेत्र और विश्व में गंभीर चुनौती की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर, ईरान के भविष्य के लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस्राइल-हमास संघर्ष पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और अपने परमाणु मुद्दे को कैसे संभालता है।

नार्वे

पृथ्वी का आखिरी देश, यहां केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है सूरज

क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि दुनिया कहां खत्म होती है। वैसे तो दुनिया गोल है, लेकिन इसका भी अंतिम छोर है, जहां देश की ही नहीं दुनिया की सीमा भी खत्म हो जाती है। यहां लोगों को रात देखना नसीब नहीं है। कहते हैं कि यहां सूरज भी सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है।

हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हर जगह कोई न कोई देश बसा हुआ है। हर देश अपने आप में खूबसूरत है। कोई देश ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है, तो कोई अपने प्राकृतिक नजारों के लिए। यूं तो आपने दुनिया के सबसे बड़े और अमीर देशों के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आखिरी देश कौन सा है।

नॉर्वे दुनिया का आखिरी देश है। माना जाता है कि यहां पृथ्वी का अंत हो जाता है। यह देश उ?तरी पोल के पास स्थित है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है, जहां पृथ्वी धुरी पर घूमती है। तो आइए जानते हैं कैसा होता है नॉर्वे का नजारा।

छोटी होती है रात

यह देश बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यहां रात नहीं होती। होती भी है तो बहुत छोटी। उ?तरी नॉर्वे की हेवरफेस्?ट सिटी में सिर्फ 40 मिनट के लिए ही सूरज डूबता है। इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं।

गर्मियों में यहां जमती है बर्फ

यह देश बहुत ठंडा है। जहां दुनिया में गर्मी के दिनों में कुछ देशों में तापमान 45 से 50 के बीच होता है, वहीं गर्मियों में यहां बर्फ जम रही होती है। इस समय यहां का तापमान जीरो डिग्री रहता है। सर्दियों में यहां का तापमान माइनस 45 डिग्री के नीचे चला जाता है। यहां पहुंचने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया का अहसास होगा।

गर्मियों में नहीं होती यहां रात

उत्तरी ध्रुव के करीब होने के कारण यहां अन्य देशों की तरह रोजाना रात या सुबह नहीं होती। बल्कि यहां छह महीने दिन तो छह महीने रात रहती है।

सर्दियों के दिनों में यहां सूरज के दर्शन तक नहीं होते, जबकि गर्मियों के दिनों में यहां कभी सूरज डूबता ही नहीं। मतलब कि गर्मी के दिनों में यहां रात नहीं होती। यह जगह इतनी दिलचस्प है कि लोग दूर-दूर से इस अनोखे नजारे को देखने के लिए जाते हैं।

अकेले जाना मना है

यह सब जानने के बाद आपका मन नॉर्वे जाने का जरूर करेगा। पर आपको बता दें कि ई-69 हाईवे धरती के सिरों को नॉर्वे से जोड़ता है। यह सड़क ऐसी जगह जाकर खत?म होती है, जहां से आगे जाने का रास?ता आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि यहां दुनिया का अंत हो जाता है। अगर आप इस हाईवे पर जाना भी चाहें, तो अकेले जाना मना है। यहां के लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना होगा और फिर यहां जाने की परमिशन लेनी होगी। इस सड़क पर किसी व?यक्ति को न तो अकेले जाने की इजाजत है और न ही अकेले गाड़ी ड्राइव करने की। यहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ऐसे में अकेले सफर करने से खो जाने का डर बना रहता है।

देख सकते हैं खूबसूरत पोलर लाइट

इस जगह पर सनसेट और पोलर लाइट्स देखना काफी मजेदार होता है। कहते हैं कि यहां सालों पहले मछली का कारोबार हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे इस देश का विकास हुआ और पर्यटकों का यहां आना शुरू हो गया। अब यहां पर्यटकों को ठहरने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट की सुविधा भी मिलती है।

थाईलैंड जाने वालों के आ गए मजा...छात्र हो या ऑफिस में कामकाजी लोग, घूमें 2 महीने बिना किसी वीजा के!

अब विदेशी पर्यटकों के लिए थाईलैंड में जाकर रहना आसान हो जाएगा। यह देश अब एम्प्लॉयी, स्टूडेंट और रिटायर्ड लोगों को लंबे समय तक यहां ठहरने की अनुमति देगा। कुल 93 देशों के लोग 60 दिन तक थाइलैंड में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं।

कोविड महामारी के बाद से दुनियाभर के देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। यहां न केवल घूमने के लिहाज से लोगों का जाना कम हुआ, बल्कि अब लोग न तो यहां रहने जाते हैं और न ही पढ़ने और जॉब करने। ऐसे में कई देशों ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नियम बनाए हैं। ज्यादातर देशों ने वीजा नियमों में छूट देने का ऐलान किया है।

वहीं अब थाइलैंड में भी लोग जाकर रह सकते हैं। अब यह देश दूरदराज के कर्मचारी, ग्रेजुएट स्टूडेंट और रिटायर हो चुके लोगों को यहां लंबे समय तक रहने की छूट दे रहा है। वीजा गाइड.वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नया निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

2 महीने रुक सकते हैं यहां

यह नियम अगले महीने से लागू होगा। इसके तहत 93 देशों के यात्रियों को 60 दिनों तक थाईलैंड में रहने की अनुमति दी जाएगी। यानी की यहां आने वाले नागरिक दो महीने आराम से यहां समय बिता सकते हैं। वहीं दूरदराज के कर्मचारियों के लिए वीजा की वैधता पांच साल तक बढ़ा दी जाएगी। इसमें हर प्रवास की सीमा 180 दिन होगी।

पिछले साल थाईलैंड में पर्यटकों की संख्या

थाईलैंड घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा और सस्ता देश है। हर साल यहां अच्छी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। बात अगर साल 2023 की करें, तो थाईलैंड में लगभग 24.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। वहीं पिछले साल, थाई सरकार ने देश में 25 से 30 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना शुरू की थी।

ईईसी एक्सपर्टस के लिए 10 साल का वीजा

इस महीने की शुरुआत में, थाईलैंड की कैबिनेट ने ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरीडोर (ईईसी) में अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए एक विशेष वीजा को मंजूरी दी है, जो दस साल के लिए वैध होगा। बता दें कि थाई सरकार ने पिछले साल नवंबर में विदेशियों के लिए ईईसी वीजा और वर्क परमिट को मंजूरी दे दी थी।

थाईलैंड में घूमने की जगह

अगर आप कुछ दिन थाईलैंड में हैं, तो फी फी आइलैंड, कोरल आइलैंड, जोमटियन बीच, अयुथया, व्हाइट टैंपल, ग्रैंड पैलेस, वाट अरुण, कंचनबुरी और खाओ सोक नेशनल पार्क जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

थाईलैंड घूमने का सही समय

वैसे तो आप सालभर कभी भी थाईलैंड घूमने जा सकते हैं। फिर भी थाईलैंड घूमने का सबसे अच्छा मौसम नवंबर से अप्रैल की शुरुआत तक है। इस समय यहां का मौसम साफ होता है। । समुद्र तट पर सैर करने या अनेक विरासत स्थलों को देखने के लिए समय उपयुक्त है।

भारत के सबसे ठंडे शहरों में बनाएं गर्मियों में घूमने का प्लान, बेहद खूबसूरत हैं ये जगह

अप्रैल-मई के महीने में गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में होती है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे मौसम में न तो बाहर जाने का मन करता है और न ही घर में रहने का मन करता है। ऐसे में अगर आप भी इस गर्मी किसी ठंडी जगह पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं। जहां पर अन्य जगहों की तुलना में काफी कम तापमान रहता है। लेकिन इसके बाद भी इन जगहों पर आपको गर्मी महसूस हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां पर आप ठंड का एहसास कर सकें। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश के कुछ सबसे ठंडे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन जगहों पर आप गर्मी में भी कंपकंपा देने वाली ठंड का आनंद उठा सकते हैं।

लेह लद्दाख

लेह लद्दाख में भी पूरे साल ठंडक बनी रहती है। यह हिमालय पर्वतमाला के बीच बसा है। सर्दी के मौसम में यहां का तापमान माइनस में चला जाता है। वहीं यह जगह गर्मियों में घूमने के लिए काफी अच्छी है। गर्मियों में यहां का तापमान 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बता दें कि मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में आप यहां पर बर्फीले पहाड़ों को देखने के साथ ठिठुरने वाली सर्दी का एहसास कर सकते हैं। लेह-लद्दाख में भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह है।

द्रास और सियाचिन ग्लेशियर

जहां अप्रैल के महीने में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगती है, तो वहीं द्रास में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। द्रास लेह लद्दाख में कारगिल जिले में स्थित है, इसको भी भारत का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। इसके साथ ही सियाचिन ग्लेशियर भी सबसे ठंडे स्थानों की लिस्ट में शामिल है। यहां पर तापमान शून्य से -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित सियाचिन ग्लेशियर एक हिमानी यानी ग्लेशियर है।

तवांग

बता दें कि सबसे ठंडी जगहों में अरुणाचल प्रदेश का तवांग शहर भी शामिल है। यहां पर सर्दी के मौसम में हिमस्खलन और भारी बर्फबारी होती हैं। वहीं गर्मियों में भी कम तापमान रहता है। तवांग की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडक पर्यटकों को गर्मी के मौसम में यहां आने के लिए प्रोत्साहित करती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार

नईदिल्ली। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के इतने दिनों बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री ने उस भाषण का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया।

लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले देश की जनता को संबोधित एक पत्र में मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि मैं इस चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी घृणित नफरत भरे भाषणों में लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं से कहा कि केवल कांग्रेस ही विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं से विकास और समावेशी प्रगति के लिए वोट देने तथा प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव को मौका देने की अपील की।

सीएम केजरीवाल की अर्जियों पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम और नियमित जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को ईडी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को शनिवार तक केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दरअसल, केजरीवाल की ओर से दो अर्जी दायर की गई है। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की है। दूसरी अर्जी में उन्होंने सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने दोनों अर्जियों पर ईडी को नोटिस जारी किया है। एक जून को दोपहर दो बजे आगे सुनवाई होगी। केजरीवाल फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया।

केजरीवाल 2 को जेल में जाएंगे वोट बर्बाद न करें : हरसिमरत

चंडीगढ़। बठिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणी अकाली दल (शिअद) की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केजरीवाल 2 जून को जेल में चला जाएगा, वो केंद्र में कभी कुछ नहीं बनेगा। कांग्रेस ने पिछली बार 545 सीट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 50 सीटें मिली थी। अब वे 325 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उन्हें 30 सीटें मिल जाएंगी। भाजपा किसानों को मारपीट रही है, किसान उन्हें खेत में भी घुसने नहीं दे रहे। आप अकाली दल को मज़बूत करें जो संसद में जाकर आपके हकों की लड़ाई लड़ें। हरसिमरत अपने दिवंगत ससुर और पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का जिक्र करते हुए मतदाताओं को याद दिला रही हैं कि वह उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए उनके बीच रहते थे। बठिंडा संसदीय क्षेत्र में एक जून को मतदान होना है।

मनीष सिसोदिया की फिर बढ़ी 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक अन्य आरोपी की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया अन्य सह-आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच में आरोपी हैं। मामले में आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पिछले साल फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एक महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। 17 मई को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है।

ईडी ने राशन भ्रष्टाचार मामले में रितुपर्णा सेनगुप्ता को भेजा समन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राशन भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता को तलब किया है। रोजवैली वित्तीय धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लगभग पांच साल बाद ईडी ने उन्हें एक बार फिर तलब किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक्ट्रेस को 5 जून को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने बैंक लेनदेन की जानकारी के आधार पर अभिनेत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले जुलाई 2019 में अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता से जांच एजेंसी ईडी ने रोजवली मामले में पूछताछ की थी ईडी सूत्रों के मुताबिक, रितुपर्णा फिलहाल अमेरिका में हैं। उन्हें बुधवार को ई-मेल के जरिये तलब किया गया था। हालांकि, ईडी के नोटिस को लेकर रितुपर्णा की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। राशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी पहले ही राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, बनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या, राशन व्यापारी बकीबुर रहमान और उनके करीबी सहयोगियों सहित सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है।

प्रधानमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला तीखा हमला

स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा 'इंडिया' गठबंधन : खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया है। खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा क्योंकि इस चुनाव में देश का हर नागरिक जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद जनता ने मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों पर वोट मांगा।

खड़गे ने दावा किया कि हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सब मिलकर इस देश को एक समावेशी राष्ट्रवादी विकासवादी सरकार देंगे और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी को लेकर मोदी के बयान पर भी उन्होंने वार किया। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में गांधी फिल्म देखकर पता चला। मुझे इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की अलग-अलग जगहों पर उनके स्टैच्यू हैं। अगर नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता हमारे इस विचार से सहमत है कि अगर इस सरकार को दोबारा मौका दिया गया तो यह लोकतंत्र का अंत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 15 दिन में भाषणों में कांग्रेस का नाम 232 बार और अपना नाम 758 बार लिया लेकिन एक भी बार भी बेरोजगारी पर बात नहीं की।

इंडिया ब्लॉक 48 घंटे के भीतर कर लेगा प्रधानमंत्री का चयन : जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक धड़े निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उसके चयन पर फैसला करने में 48 घंटे से भी कम समय लग सकता है। गठबंधन में अधिकतम सीटें उसके नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होंगी। सात चरण के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार के आखिरी दिन एक साक्षात्कार में कांग्रेस महासचिव ने विश्वास जताया कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) को 272 के आंकड़े से काफी ऊपर सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय धड़े को निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उसके चयन पर फैसला करने में 48 घंटे से भी कम समय लग सकता है। रमेश ने यह भी कहा कि जब भारतीय जनबंधन दलों को लोगों का जनादेश मिलेगा, तब एनडीए के कुछ दल गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू जैसे राजग सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पल्टी-फेस के मास्टर हैं।

पंजाब में बोले पीएम मोदी- हमारा फोकस युवाओं पर, तीसरे टर्म में अगले 125 का खाका है तैयार

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है : मोदी

चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। उससे पहले प्रचार का दौर जारी था जो गुरुवार शाम खत्म हो गया। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में गुरुवार को एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधिन में कहा कि देश में आज एक दमदार सरकार की जरूरत है। गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग मुझे नई-नई गालियां देते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि 'यही समय है, सही समय है' आज फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं- 21वी सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत में जो विकास का काम हुआ है वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों को कितनी इज्जत दी जाती है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है।

पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहती है। हमारी सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, इसका खाका तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसकी तैयारी की जा चुकी है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं पर फोकस है। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं इसकी भी रूपरेखा खींचने का काम किया जा चुका है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी 'विरासत भी, विकास भी' के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान में संकट आया तो, वहां पर हमारे जो सिख भाई-बहन भी थे। ज्यादा खतरा पैदा हुआ तो हम गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख कर अपने देश लाए। यही नहीं, हमने साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली में कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। हर भारतीय विकसित भारत के सपने से जुड़ा है, हमें आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। बीजेपी सरकार के सत्ता में लौटने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के हैट्रिक बनाने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि पंजाब के जालंधर जिले में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाए।

जिस दिन मुंह खुलेगा, तुम्हारी सात पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामें किए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। यहां तो आमने-सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। इसलिए इन्होंने भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से भ्रष्टाचार के पाठ बराबर पढ़ लिए हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामें दुनिया देख रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं... इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एससी-एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का रहा है। ये संविधान की भावना का, बाबा साहब अंबेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और मोदी को लगातार नई-नई गालियां देते रहते हैं। मोदी ने कहा कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी सात पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा।

वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोदी ने लिखा पत्र, मतदान करने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के पहली बार मतदाताओं को लिखे पत्र में उनसे 1 जून (शनिवार) को होने वाले लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में वोट डालने की अपील की है। भाजपा के कार्यकर्ता वाराणसी के प्रत्येक इलाके में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अभिनंदन पत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पत्र पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में लगभग 31,538 पहली बार मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र में लिखा कि भारत के प्रधान सेवक और आपके सांसद के रूप में, आज मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ आपको लिख रहा हूं। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी ओर से आपको बधाई हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का यह अवसर एक विशेषाधिकार है जो राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी का गवाह बनेगा क्योंकि लोकतंत्र न केवल शासन का एक रूप है बल्कि हमारी स्वतंत्रता की आधारशिला भी है। वह आगे लिखते हैं, आप साक्षी हैं कि पिछले 10 वर्षों में वाराणसी ने किस प्रकार विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 विश्व कप से पहले भारत आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1

नईदिल्ली। भारतीय टीम जल्द ही टी20 विश्व कप खेलते हुए नजर आएगी। टी20 विश्व कप की शुरुआत 1 जून से हो रहा है। अमेरिका और वेस्टइंडीज की सह-मेजबानी में आयोजित होने की वजह से भारतीय समयानुसार ये मुकाबला भारत के लिए दो जून से होगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलकर करेगी। वहीं भारतीय टीम 9 जून को अपने चीर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलती हुई नजर आएगी। बता दें, होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को 1 जून को बांग्लादेश के साथ एक अभ्यास मुकाबला भी खेलना है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने रैंकिंग जारी की है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक, भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है। वहीं पाकिस्तान का नाम टॉप-5 की लिस्ट से बाहर है। टीम इंडिया इससे पहले भी इस सूची में पहले स्थान पर काबिज थी। ताजा रैंकिंग में भी अपनी जगह पहले स्थान पर पाकर टीम के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर काबिज है।

भारतीय टीम इस सूची में 264 रेटिंग के साथ अपनी जगह पहले स्थान पर बनाई हुई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया 257 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। इसके आगे टी20 वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड 254 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर है। फिर वेस्टइंडीज 252 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर आती है। वेस्टइंडीज ने दो पायदान की छलांग लगाते हुए नंबर 4 पायदान हासिल किया। फिर न्यूजीलैंड 250 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान टॉप-5 में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी है। पाकिस्तान टीम 244 रेटिंग के साथ छठे पायदान पर है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 244 रेटिंग के साथ सातवें पायदान पर है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 617 अंक फिसला निफ्टी 22,489 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लगातार पांचवें ट्रेडिंग सेशन में गिरकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच लोक सभा चुनाव के नतीजों से पहले निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पिछले बंद भाव के मुकाबले गिरावट में खुला और इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान 73,668.73 अंक तक लुढ़क गया। अंत में सेंसेक्स 0.83 प्रतिशत या 617.30 अंक की गिरावट लेकर 73,885.60 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.95 प्रतिशत या 216.05 अंक की गिरावट के साथ 22,488.65 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट टाटा स्टील के शेयर में रही जो 5.84 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।

स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने अग्निबाण को किया सफलतापूर्वक लॉन्च

श्रीहरिकोटा। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण एसओआरटीईडी-01 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इसरो ने भी इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद इसे एक प्रमुख मील का पत्थर करार दिया है। इसरो ने अग्निकुल कॉसमॉस को इस सफलता और उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। इसकी खासियत है कि ये दुनिया का पहला 3डी रॉकेट है। ये एक सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसके इंजन का नाम अग्निलेट इंजन है। ये 3डी प्रिंट से तैयार हुआ इंजन है। इस इंजन की खासियत है कि ये 6 किलोन्यूटन की ताकत पैदा कर सकता है। इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। बता दें कि पारंपरिक गाइड रेल के जरिए इसे लॉन्च नहीं किया गया है।

वित्तवर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 7% रहने का अनुमानः आरबीआई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष (2024-25) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। आरबीआई ने 30 मई को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि मुद्रास्फीति के निर्धारित स्तर की ओर बढ़ने से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग मांग में तेजी आएगी। रिपोर्ट के अनुसार बाह्य क्षेत्र की मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू आर्थिक गतिविधियों को वैश्विक प्रभावों से बचाएंगे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक जिंस मूल्य में उतार-चढ़ाव, अनिश्चित मौसमी घटनाक्रम वृद्धि की संभावनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करते हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बैंकों और कॉरपोरेट जगत की मजबूत बैलेंस शीट से समर्थित ठोस निवेश मांग के दम पर जीडीपी वृद्धि मजबूत है।

जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य कोटेड स्टील खंड में 50% बाजार हिस्सेदारी हासिल करना

नईदिल्ली। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जिंक-मैग्नीशियम-एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोटेड इस्पात पेश करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। कंपनी का लक्ष्य एक साल के भीतर इस खंड में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। जेएसडब्ल्यू समूह के प्रवक्ता ने बताया कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सुविधाओं में प्रति वर्ष नौ लाख टन की कोटेड क्षमता स्थापित करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रवक्ता ने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य भारत में मैग्श्योर को पेश करने के एक वर्ष के भीतर इस कोटेड खंड में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। यूरोप और पश्चिम एशिया में भी जेएसडब्ल्यू मैग्श्योर के लिए निर्यात अवसरों की तलाश कर रही है।

आर्थिक मोर्चे पर भारत का सुनहरा भविष्य

(गतांक से आगे...)

उमेश चतुर्वेदी

चार जून को आने वाले चुनाव नतीजों के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी। विपक्षी दलों ने अपनी नीतियों में आर्थिक मोर्चे पर कुछ समाजवादी और वाम वैचारिकी प्रेरित योजनाएं लाने का वादा जरूर किया है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह आगे बढ़ चुकी है, उसमें उनके लिए भी कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्हें भी मौजूदा आर्थिक चलन के ही मुताबिक आगे बढ़ना होगा। भले ही वे जीएसटी को कम करने या उसका ढांचा सुधारने का वादा करते रहे हों, लेकिन उनके लिए भी आमूलचूल बदलाव ला पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि इस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद आगे बढ़ चुकी है।

भारत सदियों से कृषि संस्कृति वाला देश है। भारत की दो तिहाई आबादी सीधे खेती-किसानी से जुड़ी है। भारतीय खेती मानसून की बेहतरी पर ज्यादा निर्भर है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले साल में मानसून सामान्य रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगले साल भी खेती - किसानी में बेहतर स्थिति रहेगी। उत्पादन बढ़ेगा और इसकी वजह से भारत के अन्न भंडार भरे रहेंगे। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में खरीद में तेजी आएगी। मानसून बेहतर रहता है तो भारत के दूर- दराज के बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज रहती हैं। इसकी वजह से भी भारतीय आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी।

भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता भी दुनिया की नजरों में और आकर्षक हो सकती है। इसकी वजह से नए

तरह की उत्पादकता भी भारत में दिख सकती है। सभ्यता, संस्कृति, तीर्थाटन और पर्यटन के साथ ही भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था और योग भारत की अनुपम संपत्ति हो सकते हैं। इसे देखते हुए भारत की मौजूदा सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचा को पहले की तुलना में बेहतर करना शुरू किया है। कोरोना काल के हालात की वजह से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय ज्ञान परंपरा, योग आदि की भी दुनिया में मांग बढ़ी है। दुनिया इनकी ओर उम्मीदभरी नजरों से देख रही है। इनकी वजह से भारत में विदेशों से धन भी आ रहा है। भारतीय तीर्थाटन की परंपरा को राम मंदिर, महाकाल मंदिर और विश्वनाथ कारीडोर जैसे नए मंदिरों और धार्मिक केंद्रों की ओर दुनियाभर से आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से बुनियादी ढांचे और पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इनके जरिए भी तेजी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय पर्यटन केंद्रों की अभी तक पूरी तरह से वैश्विक पहचान और ध्यान नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में अभी काम किया जाना बाकी है। नए भारत में इस दिशा में भी सोचा जाना होगा। जब इनकी ओर ध्यान जाएगा, तो वैश्विक यात्रियों और सैलानियों की आवक तेज होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इसकी भी बड़ी भूमिका होगी।

इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत लिखकर भारत की इस समृद्ध परंपरा की महत्ता को ही दिखाने की कोशिश की है। प्राचीन काल में भारत की हैसियत विश्व गुरू की थी। भारत एक बार फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने की ओर है। दुनियाभर में फैला भारतीय डायस्पोरा भी भारत को सालाना सौ अरब डॉलर से ज्यादा की रकम घर भेज रहा है। साल 2023 में यह रकम सवा सौ अरब डॉलर थी। जाहिर है कि सब मिलकर भारत को समृद्ध कर रहे हैं और भारतीय जीडीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। दस साल से देश संभाल रही मोदी सरकार इसे और तेज करना चाहती है। यही वजह है कि पहले सौ दिन का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। आने वाली सरकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानों से कहीं अधिक तेज प्रदर्शन का दबाव रहेगा। क्योंकि मौजूदा चुनावों में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा रही है। मौजूदा आर्थिकी के मुताबिक, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। जाहिर है कि नई सरकार नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे पर वह कठघरे में खड़ा हो।

कवर्धा पिकअप हादसे के मृतकों के परिजनों से मिलने उनके गांव सेमरहा पहुंचे मुख्यमंत्री साय कहा-

आप हमें अपना समझें, संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है

रायपुर/कबीरधाम। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कबीरधाम जिले के कुकदूर के ग्राम सेमरहा पहुंचे। जहाँ उन्होंने ग्राम बाहपानी में हुए दु:खद हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार के लोग भावुक हो उठे और एक-एक कर अपने दु:ख को साझा किया। श्री साय ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें संबल प्रदान किया और संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही।

सीएम साय ने परिजनों से कहा कि - आज का दिन बहुत ही दु:खद है। जो घटना घटी उसके लिए हम सब दु:खी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मैंने गृहमंत्री विजय शर्मा से कहा कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए और वहां जो भी त्वरित मदद हो सके वह करिये। जिस पर गृहमंत्री जी रायपुर से तत्काल वहां पहुंचे और पीड़ित परिवारों व घायलों की आवश्यक मदद की। हमारे अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। यहाँ की स्थानीय विधायक ने भी मुझे फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। यह घटना वास्तव में दु:खद है और एक ही परिवार के दस सदस्यों का एक साथ चले जाना दु:ख के पहाड़ के समान है। दुर्घटना में गई जान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती, हम लोग सांत्वना ही दे सकते हैं।

श्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और छत्तीसगढ़ सरकार भी आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार की तरफ से हमनें पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जो जल्द ही आप लोगों को दी जाएगी। यह अच्छी बात है कि पंडरिया विधायक ने मृतक परिवार के छोटे बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार मृतक परिवारों के हित के लिए जो कर सकती है उसे हम अवश्य करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि मृतकों की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

गौरतलब है कि विगत 20 मई को कबीरधाम जिले के कुकदूर के बाहपानी गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए श्रमिकों से भरी पिकअप के पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई थी और कई श्रमिक घायल हो गए थे। घटना के बाद मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फोन पर बात की थी। आज श्री साय पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव पहुंचे और उनके दु:ख में शामिल होकर उन्हें ढांढस बंधाया।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही विष्णुदेव सरकारः शर्मा

दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत में 85 सड़कें निर्माण हेतु चिन्हित, 40 सड़कों का निर्माण प्रगति पर, 11 सड़कें पूर्ण

रायपुर। उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस शासन में सड़कों का निर्माण रुका पड़ा था। हमारी सरकार बनी तो मात्र 4 माह के अल्प समय में हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 11 सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, और पहली बार इन विभागों की समन्वित रणनीतिक कार्यशैली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। उप-मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा को लेकर थी।

इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयास हमने यह किया कि इसके लिए योजना बनाकर अब संयुक्त बैठक प्रारंभ की है, जिसमें गृह विभाग और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठते हैं। इसमें एडीजी नक्सल विवेकानंद, आईजी एसआईबी ओपी पाल और पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक रायपुर व दंतेवाड़ा में विभागों की संयुक्त बैठक लेकर सड़कें चिन्हित करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं और के.के. कटारे के नेतृत्व में निर्माण तेजी से पूर्ण कराते हैं। संयुक्त बैठकों में अब तक कुल 85 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 259.90 किलोमीटर की 40 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। यह सभी सड़कें दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। यह विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है। यह विषय महत्वपूर्ण कि अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र जहां आजादी के बाद आज तक शासन नहीं पहुंच पाया वहां सर्वे करके केंद्र सरकार की जनमन योजना के तहत 09 सड़क स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 04 का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही 06 और सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। पुलिस बल की सुरक्षा में जिन 11 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है उनमें कांकेर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव जिला अंतर्गत एक-एक सड़क, दंतेवाड़ा जिले में 03 सड़क तथा सुकमा जिले में 05 सड़कें शामिल हैं। इनमें कांकेर जिले में किसकोड़ो से कोटखुरसाई तक, भानुप्रतापपुर जिले में बड़गांव प्रतापपुर रोड बड़ेझारकट्टा तक, कोंडागांव जिले में कोंडागांव कोरमेल रोड से स्कूल पारा मातवाल से गुनिया पारा कुदुर तक, जिला दंतेवाड़ा में सुरनार से पटेल पारा तक, कोरीरास किद्रीरास रोड से छोटेबेडमा तक, कवलनार से झिरका तक, जिला सुकमा में डोलेरास से पेडलनार तक, धनिकोडाता से डेंगोपारा तक, कांहीगुड़ा मार्ग, चिकपल्ली मार्ग, मोशलपारा से सोब्बीरासपारा तक सड़क निर्माण पूर्ण किया गया है।

छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी। लेकिन मानसून ने 2 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है, इसलिए प्रदेश में भी दो दिन पहले ही बारिश की आशंका जताई जा रही है।

तापमान बढने से दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने लगी

रायपुर। नौतपा के छठवें दिन भले ही सूर्यदेव धूप और छांव का खेल खेल रहे थे लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रचंड गर्मी ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं और गर्म हवाओं के चलते सड़कें सूनी होने लगी है। तापमान बढने से दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने लगी है। लोग गर्मी और लू से बचने गमछा, टोपी, चश्मा समेत अन्य तरह के उपाय कर घरों से निकल रहे हैं। सूरज की किरणें आग बरसा रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक गर्म हवाओं और सूर्य की तपिश के चलते लोग घरों में दुबकने मजबूर हो गए है। झुलसाने वाली सूर्य की किरणों से बचने के लिए लोग चेहरे में स्कार्फ व सिर में टोपी का उपयोग कर रहे हैं। दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह सूनसान नजर आने लगा है। तेज गर्मी और लू के चलते बाजार इलाके में सन्नाटा पसरने लगा है।

बढ़ती गर्मी के चलते मुख्यमंत्री का लोगों से आग्रह, सावधानी बरतें

रायपुर। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही है। श्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ङ्क पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि - प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं। जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकले, धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें, पानी अधिक मात्रा में पियें, अधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस घोल पियें, छायादार जगहों पर रहें, लू लगने या तबियत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं। क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक हीटवेव के जारी रहने की बात कही है। जिसके चलते सीएम साय ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

लालू के चारा घोटाले को कांग्रेस सरकार ने पीछे छोड़ा, मछली पालन में भी घोटाला कर डाला

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों में बड़ी लूट की हर वर्ग का हक मारा- कश्यप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के मछली पालन के नाम पर एक नए घोटाले के ताजातरीन खुलासे के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने वाले नक्सल बजट से मत्स्य विभाग में बड़ा खेल पिछली भूपेश सरकार ने करके मछली पालन के केज बनाने में घोटाला तो किया ही, उस योजना की सब्सिडी किसान की जगह फर्म को दे दी।

कश्यप ने कहा कि प्रदेश में गोबर के नाम पर शर्मनाक घोटाला करने वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने मछली पालन के केज तक में भी घोटाला करके अपने भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र का एक और काला अध्याय अपने शासनकाल में रचा है।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए आए बजट को मछली पालन के केज बनाने की सब्सिडी में खर्च कर दिया गया। यही नहीं, सब्सिडी किसानों के खाते के बजाय सीधे फर्म को भेजने का कारनामा करने वाला अधिकारी आज मछली पालन कर रहा है।

श्री कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने यह कारनामा उस फंड में कर दिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास और रोजगार के लिए भेजा गया था। कांग्रेस शासनकाल में किसानों के उत्थान के नाम पर आई रकम से अफसर और कर्मचारियों ने अपना उत्थान कर लिया। राजनांदगांव में पिंजड़े में मछली पालन (केज कल्चर) के नाम पर करीब 5 करोड़ का घोटाला सामने आने को बेहद गंभीर बताते हुए श्री कश्यप ने कहा कि सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन भी ऐसा कि न तो मछली का पता और न ही तालाब में लगे केज का। केज कल्वर के नाम से अनुदान की रकम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि अजा-जजा समाज के लोगों का हक कांग्रेस ने मारा और

भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल होगा-केदार कश्यप

इसका जीता-जागता उदाहरण यह मामला है। ऐसे कई मामले हैं जो चीख-चीखकर यह बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की नुमाइंदगी में चहुँओर किस तरह लूट मची थी! छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कि भ्रष्टाचारी सरकार ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला ,गोबर घोटाला ,डीएफ घोटाला, राशन घोटाला और ऐसे कई घोटाले करने के बाद मछली पालन के नाम पर भी घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी ने यह ठान लिया था कि छत्तीसगढ़ के लोगों की पाई पाई को लूट लेंगे भाजपा की सरकार में सभी लुटेरों का बराबर हिसाब होगा।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

शराब दुकान से करीब 37 लाख चोरी करने वाले 4 पकड़ाए

रायपुर। खमतराई के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विदेशी शराब दुकान से 36,76,120 नगद चोरी करने वाले 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन युवकों ने तीन लाख रूपए खर्च कर दिए थे और उनसे चोरी के 33,57,650 रूपये जब्त किए गए। चारो युवक दुकान में ही काम करते थे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अमित शर्मा की कंपनी शराब दुकान में प्लेसमेंट के माध्यम से लोगों को नौकरी पर रखती है। कंपनी ने रोशन कन्नौजे मुख्य विक्रयकर्ता, कृष्ण कुमार बंजारे एवं साहेब लाल बंजारे सेल्स मेन थे। मनमोहन आडिल शराब दुकान में गार्ड के रूप में काम करता था। 28 मई को शराब दुकान में एक व्यक्ति के मारपीट करने के कारण चारों पैसा चोरी करने की नियत से मुख्य विक्रेता के साथ सांठ-गांठ कर मुख्य विक्रेता व अन्य लोगों के साथ व्यक्ति के विरूध्द रिपोर्ट करने थाना खमतराई आये। तथा साहेब लाल, कृष्ण कुमार व मनमोहन तीनों मिलकर दुकान के अंदर रखी बिक्री रकम 36,76,120 रूपये जो कई दिन की थी। बोरी में भरकर लेकर चले गये। मुख्य विक्रेता रोशन कन्नौजे जान बुझकर उन लोगों के साथ मिलकर तिजोरी की चाबी दुकान में ही छोड़कर चला गया था और गार्ड मनमोहन आडिल ने फोन से सूचना मुख्य विक्रेता को देने पर मुख्य विक्रेता पुलिस वाले को शराब दुकान में लूट हो गयी है कुछ लोग मारपीट कर पैसा लूट रहे है बताया।

छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने समाजिक समावेशन कार्य समूह की बैठक सम्पन्न

रायपुर। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग द्वारा विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किये गये हैं। आज यहां नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की। बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी शामिल हुए। प्रमुख सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सोनमणि बोरा ने विभागीय प्रस्तुतीकरण देते हुए विभाग के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की।

गर्मी का कहर, प्रदेश में समर कैंप स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासन के आदेश से हर साल की तरह ही इस साल भी स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बच्चों की सेहत का खयाल रखते हुए प्रदेश में आयोजित सभी समर कैंप्स को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश दिये हैं। दरअसल, राज्य में लगातार 3 दिनों से तापमान में वृद्धी देखी गई है।

बुधवार को प्रदेश का तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड से अधिक है। वहीं आज गुरुवार को मौसम विभाग ने भी प्रदेश में लू यानि हीट वेव का अलर्ट जारी किया था। जिसके बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए समर कैंप्स को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। बता दें, विद्यार्थियों में रचनात्मक बहुमुखी विकास के लिए स्कूलों में समर कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया। बहुत से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम पर घर के लिए सजावट के सामान बनाने भी सीखे। समर कैंप्स में बच्चों ने मेहंदी, रंगोली, कढ़ाई, क्ले आर्ट, पेंटिंग और अन्य कलाएं सीखी जिससे वे भविष्य में अपनी कला से आमदनी भी कमा सकेंगे।

रामगोपाल अग्रवाल के समधी के घर ईडी की रेड

रायपुर। कई घोटालों में फरार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के समधी के घर ईडी ने रेड मारी है। यह रेड रायपुर से सटे खरोरा में पड़ी है। जहां ईडी के दर्जनों अफसर पहुंचे है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बता दें कि भूपेश बघेल के सीएम रहते रामगोपाल अग्रवाल ने कई घपले-घोटाले किए है। जब सरकारी एजेंसियों को शिकायत मिली तब घपले घोटालों का खुलासा हुआ। जिसके बाद से रामगोपाल अग्रवाल फरार है। शराब, कोयला और मिलिंग घोटाला में करोड़ों रुपए गबन कर चुके है। फ़िलहाल ईडी , आईटी और ईओडब्ल्यू, एसीबी इस घोटालों की जांच कर रही है। इसमें लिप्त आईएएस और राज्य सेवा के अधिकारी जेल में बंद है। सभी घोटालों के पैसे से अचल संपत्ति खड़े किये है। जांच से बचने अपने रिश्तेदारों के नाम पर महँगी गाड़ियां और बेशकीमती जमीन खरीदे है। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष है। उनके कारनामें सामने आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा रामगोपाल अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ईडी -आईटी जांच शुरू होते ही रामगोपाल अग्रवाल फरार है। जांच एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हुई है।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी आज

रायपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल भाठागांव और रेल्वे स्टेशन रायपुर के मुख्य प्रवेश द्वार क्रमांक-दो में 31 मई को एक दिन के लिए नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य देखा जा सकता है। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। रेल्वे स्टेशन में आयोजित नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक राजेश मूणत, अपर कलेक्टर श्रीमती निधि साहू, डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर राकेश सिंह, स्टेशन डायरेक्टर एन.के.साहू और रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी करेंगी। इसी तरह अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ विधायक मोतीलाल साहू और नगर निगम के उपायुक्त विनोद पाण्डे करेंगे। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति का सन्देश देने के लिए रंगीन चित्रों तथा पोस्टर्स के माध्यम से तम्बाकू के अलावा गुड़ाखू, बीड़ी, सिगरेट और शराब आदि नशीली चीजों से स्वास्थ्य को होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सचेत किया जाएगा। इसके साथ ही राजयोग साधना के द्वारा हमेशा के लिए दुर्व्यसनों से मुक्त होने के उपायों को बहुत ही सरल शब्दों में रोचक ढंग से दर्शाया जाएगा। यह प्रदर्शनी सभी नागरिकों के लिए दर्शनीय है।

अमृतकाल- छत्तीसगढ़ विजन @2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की

कृषि एवं वानिकी विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य पर दिए सुझाव

रायपुर। अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने कृषि एवं वानिकी विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। कृषि एवं वानिकी से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। छत्तीसगढ़ को भारत में सुपर फूड का केंद्र बनाने, छत्तीसगढ़ को प्रसंस्कृत सुपरफूड का पावर हाउस बनाने, वानिकी उत्पादों के साथ मजबूत ब्रांड का निर्माण करने, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का कार्यान्वयन, कौशल उन्नयन और बुनियादी ढांचे में निवेश, फसलों

का पैदावार बढ़ाने, मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए बागवानी पर ध्यान केंद्रित करने, कृषि सेवा केन्द्र को बढ़ाने, किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा जांच तथा छत्तीसगढ़ को जड़ी बूटी और वनोपज के केंद्र के रूप में विकसित करने, वनोपज व्यापार केंद्र बनाने, भंडारण प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने, किसानों को सक्षम बनाने राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल, लघु वन उपजों की मजबूती ,जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए। अजय सिंह ने कृषि भूमि के बेहतर उपयोग एवं बहु फसल प्रथाओं को बढ़ाने की क्षमता, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बेहतर ऋण की सुविधा, उन्नत तकनीकी की आवश्यकता उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए सटीक खेती जैसे विषयों को डाक्यूमेंट में शामिल करने की बात की। सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव और सदस्य के. सुब्रमण्यम ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में बड़ा निवेश करने, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देने, जैविक खेती, फसल चक्र ,खाद्य वितरण प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज को मजबूत करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपना सुझाव दिए।

मुख्य न्यायाधीश ने लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का किया निरीक्षण

रायपुर। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिट, सिविल एवं क्रिमिनल शाखा में

औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 7 जून तक चल रहे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्य न्यायाधीश सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि वादकार, पक्षकार व्यर्थ मुकदमेबाजी से बच सकें। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, ताकि चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई के पश्चात निराकृत किया जा सके। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार रिट क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर उन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी कर रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.